

आर्थिक समीक्षा 2022-23 मुख्य विशेषताएं

आर्थिक समीक्षा 2022-23 की 'मुख्य विशेषताओं' का उल्लेख अब एक अलग दस्तावेज में किया गया है, जिसमें समीक्षा के बारह अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय के मुख्य पहलुओं को क्रम से संकलित किया गया है। 'मुख्य विशेषताओं' को चार्ट, इन्फोग्राफिक्स, तालिका और पाठ के न्यूनतम उपयोग के माध्यम से बताया गया है, इस दस्तावेज में कुल 33 पृष्ठ हैं। इन मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में इस दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इनको सरलता से समझा जा सके।

मुझे आशा है कि पाठक "मुख्य विशेषताओं" के इस दस्तावेज को समझेंगे और गहन अध्ययन के लिए आर्थिक समीक्षा में प्रासंगिक सामग्री का पता लगाने के लिए प्रेरित होंगे।

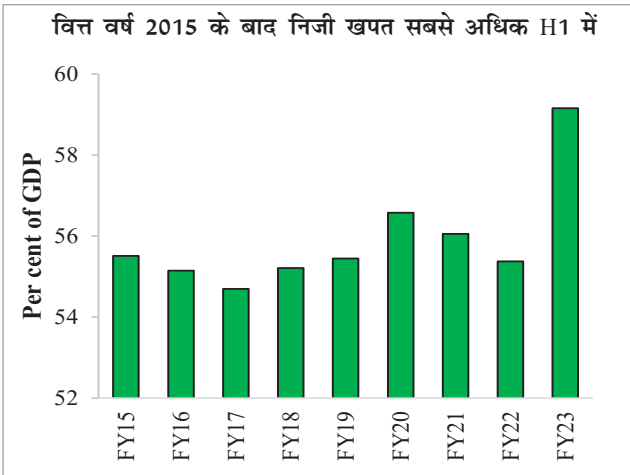
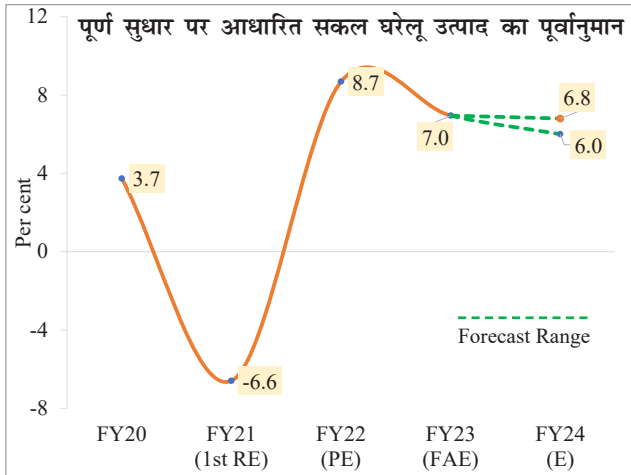
वी. अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

CONTENTS

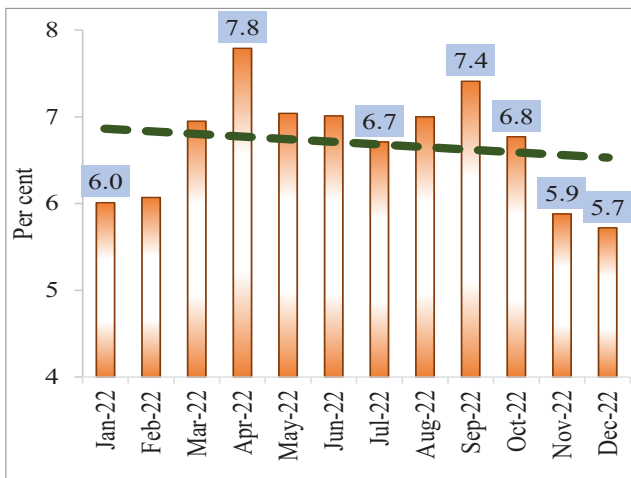
1. अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23: पूर्ण सुधार	03
2. मध्यावधि स्थिति : आशावादी तथा विश्वसनीय	05
3. राजकोषीय लाभ: राजस्व सुधार	07
4. मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: एक अच्छा वर्ष	10
5. कीमतें और मुद्रास्फीति: कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना	12
6. सामाजिक अवसंरचना और रोजगार: व्यापक व्यवस्था	15
7. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण: भविष्य का सामना करने की तैयारी	18
8. कृषि और खाद्य प्रबंधन: खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक	21
9. उद्योग: स्थिर वसूली	24
10. सेवाएं: क्षमता के स्रोत	27
11. वैदेशिक क्षेत्र: सतर्क और आशावादी	29
12. अवसंरचना विकास के लिए सरकार का दृष्टिकोण	31

अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23: पूर्ण सुधार

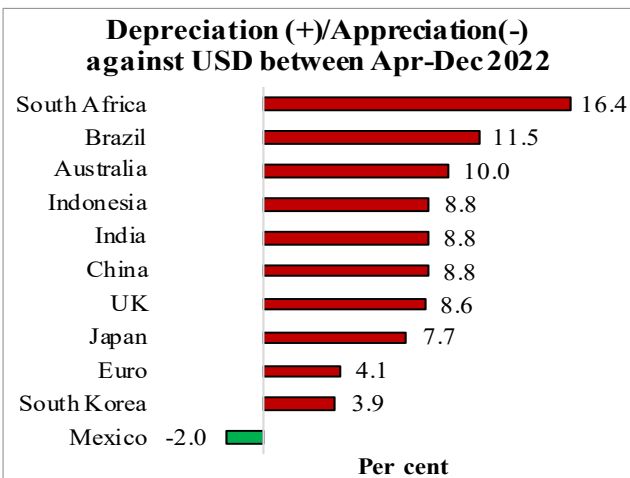
वित्त वर्ष 24 में मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की जीडीपी वृद्धि मजबूत रहने की आशा है



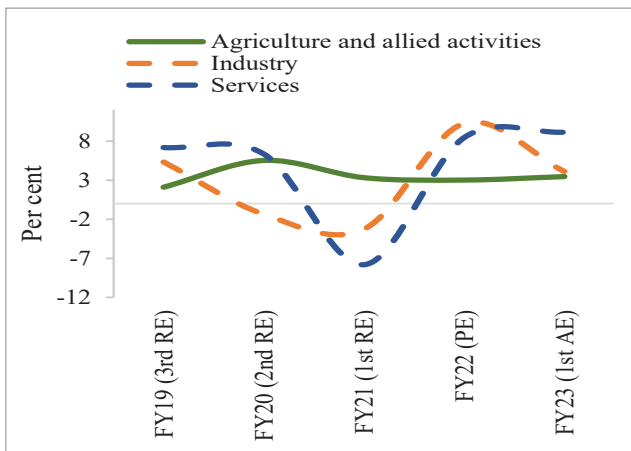
सीपीआई मुद्रास्फीति आरबीआई की लक्षित सीमा में



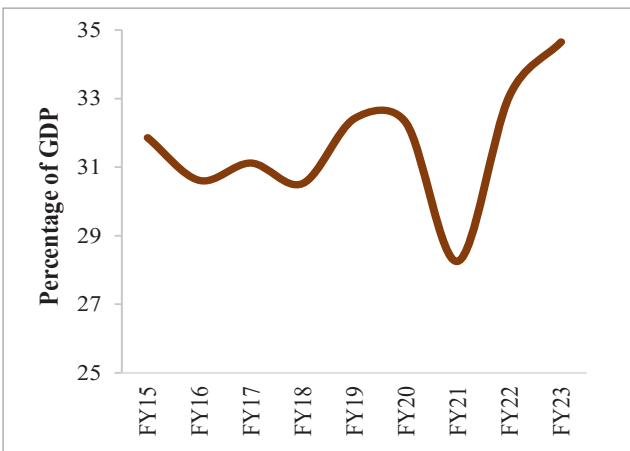
भारतीय रुपये का अन्य ईएमई की तुलना में अच्छा प्रदर्शन



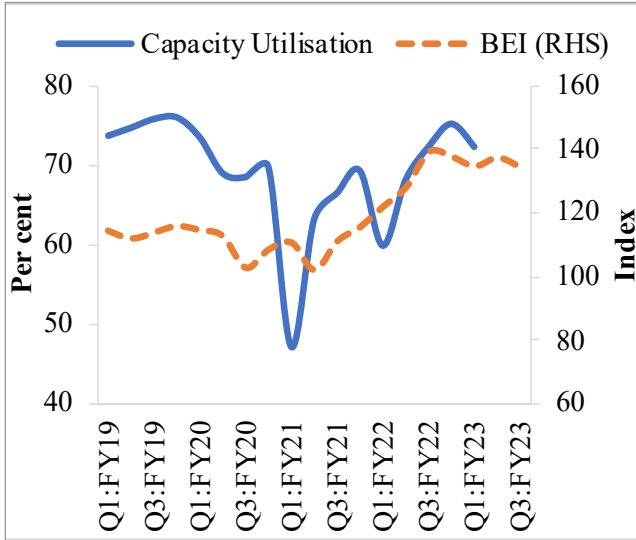
क्षेत्रों में व्यापक सुधार



वित्त वर्ष 2015 के बाद से पहली छमाही में सबसे अधिक सकल स्थिर पूंजी निर्माण

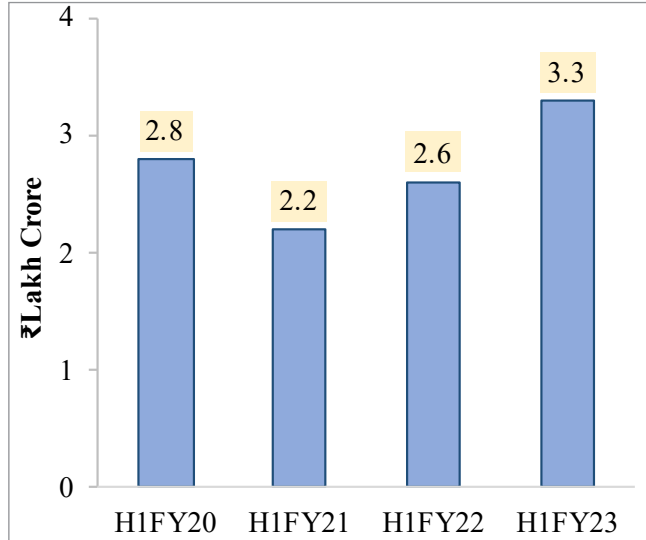


क्षमता का इष्टतम उपयोग



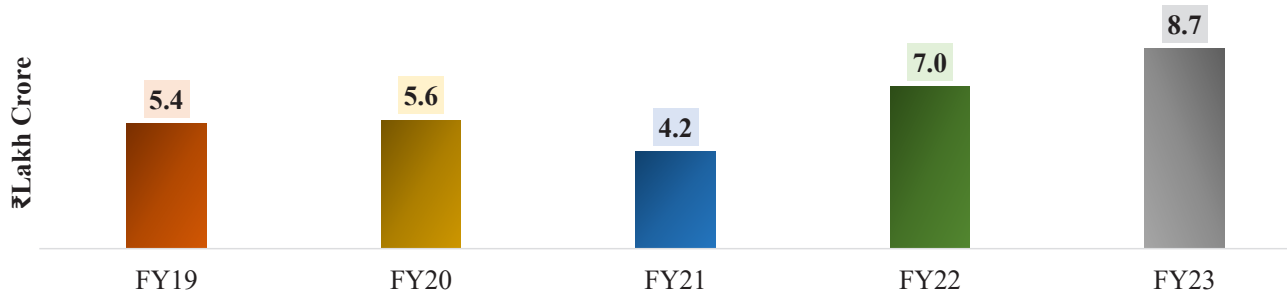
BEI: Business expectation index

निजी कैपेक्स में वृद्धि

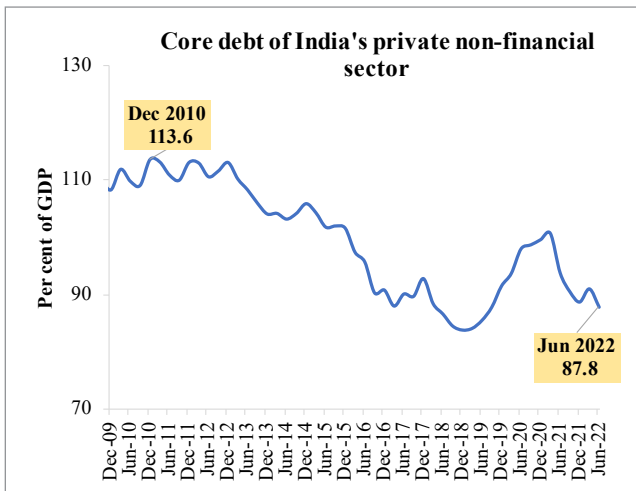


Source: Axis Bank Research, Capital Line

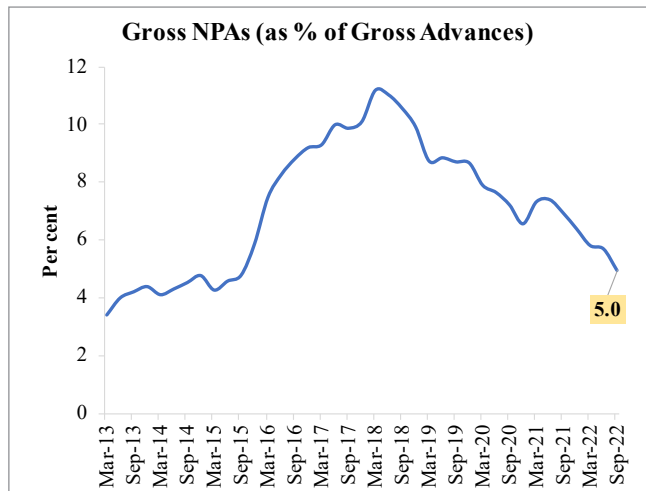
अप्रैल-नवंबर की अवधि के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि



भारत ने पिछले दशक में अपने विकास का भुगतान किया



Source : BIS

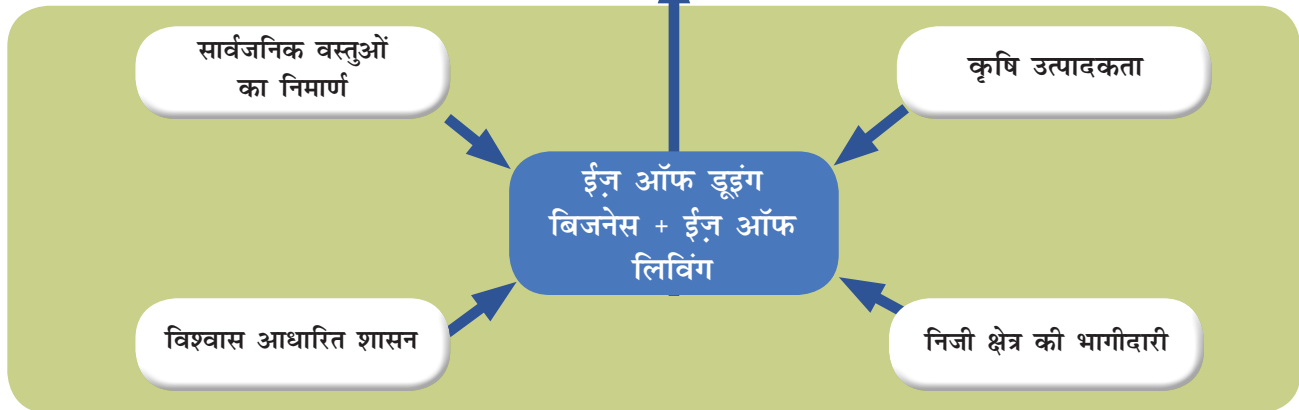


मध्यावधि स्थिति : आशावादी तथा विश्वसनीय

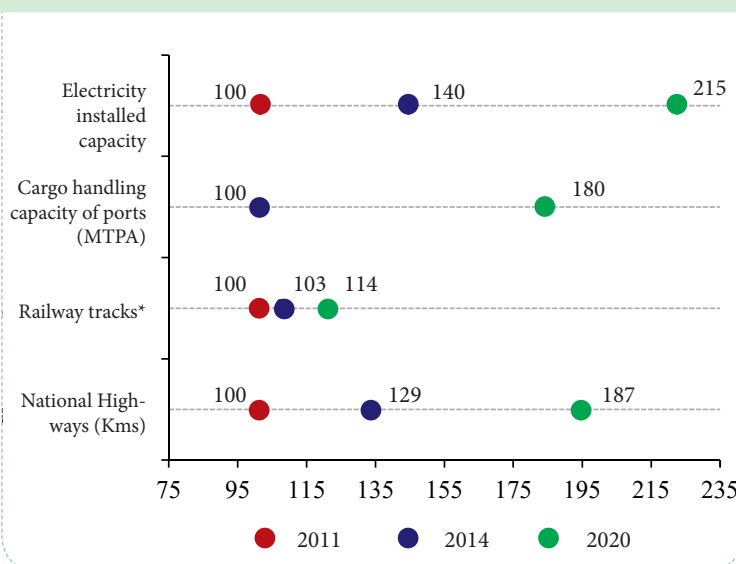
2014-2022 - नए भारत के लिए सुधार - सबका साथ सबका विकास

अर्थव्यवस्था और देश के लोगों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना

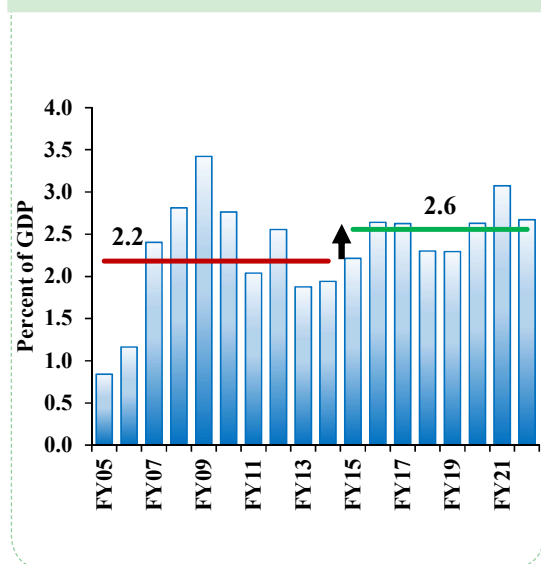
कुशल संसाधन आवंटन



भौतिक अवसंरचना में सुधार



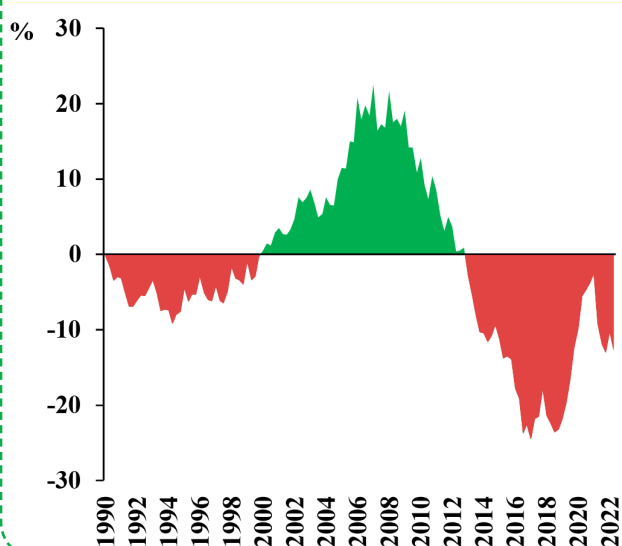
सकल एफडीआई/जीडीपी में ढांचागत बदलाव



1998-2002 और 2014-2022 की अवधि के बीच समानता

1998-2002	2014-2022
अर्थव्यवस्था में बदलाव	
<ul style="list-style-type: none"> परमाणु उपकरण परीक्षण 1998; प्रतिबंधों का पालन किया। बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा बैलेंस शीट की मजबूती और सुधार। लगातार दो सूखे प्रौद्योगिकी विफलताएं; अमेरिकी मंदी और 09/11 	<ul style="list-style-type: none"> बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैलेंस-शीट तनाव की अवधि। अभूतपूर्व महामारी, इसके बाद वैश्विक कमोडिटी मूल्य की मुद्रास्फीति, इसके बाद वित्तीय स्थिति को कड़ा होना।
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार	
<ul style="list-style-type: none"> ब्याज दर अविनियमन निजीकरण बैंकों के लिए परिसंपत्ति की वसूली अवसंरचना (स्वर्णिम चतुर्भुज) एफआरबीएम अधिनियम 	<ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट पहचान वित्तीय समावेशन जीएसटी द्वारा फॉर्मलाइजेशन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता निजीकरण कर दरों का युक्तिकरण और कर प्रशासन सुधार दोषों को अपराध की श्रेणी से बाहर बाजार में वैक्सीन आना व्यय प्रबंधन सुधार आत्मानिर्भर भारत सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना
विकास की वापसी	
<ul style="list-style-type: none"> एक झटके से विकास की गति रूक गयी झटके का प्रभाव कम होते ही संरचनात्मक सुधारों ने 2003 के बाद से विकास लाभांश का भुगतान किया 	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय क्षेत्र में बैलेंस शीट मजबूत; कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत अंक (ऋण/जीडीपी अनुपात) की कमी वैश्विक झटकों से निपटने के दौरान व्यापक (मैक्रो इकोनॉमिक्स) आर्थिक स्थिरता पर जोर

2010-2019 के दशक में क्रेडिट टू जीडीपी गैप नकारात्मक रहा: अब बैलेंस शीट की मरम्मत की जा रही है



Source: BIS

आने वाले दशक के लिए ग्रोथ मैग्नेट



बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र स्वस्थ और पुनर्पूजित क्षेत्र



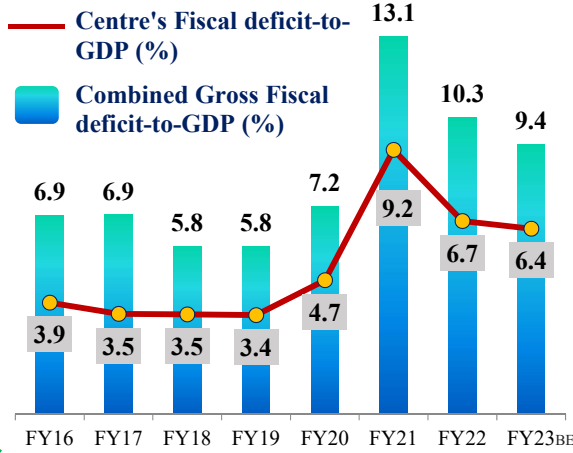
वित्तीय समावेशन, औपचारिक (फॉर्मलाइजेशन) के माध्यम से दक्षता लाभ के लिए अग्रणी डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक सुधार।



प्रतिकूलता कम होते ही भारत मध्यम अवधि में अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ने के लिए तैयार है

राजकोषीय लाभ-राजस्व सुधार

वित्त वर्ष 21 में चरम पर पहुंचने के बाद, राज. कोषीय घाटा समेकन पथ पर है



वित्त वर्ष 23 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है



संतुलित बजट अनुमान अनिश्चित समय में सुरक्षा प्रदान करते हैं



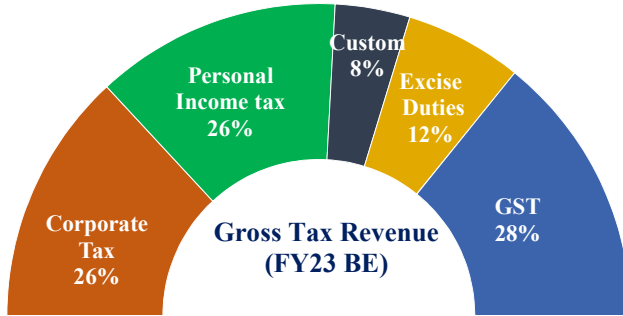
मजबूत राजस्व और विवेकपूर्ण व्यय राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं



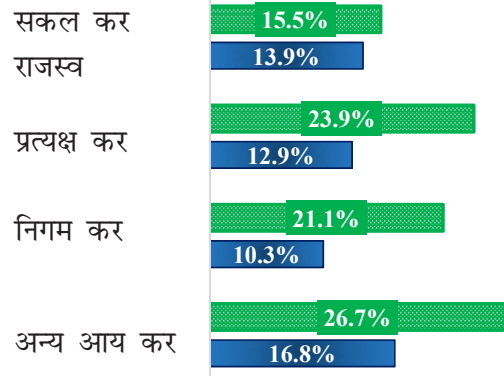
सकारात्मक विकास-ब्याज अंतर के साथ सरकारी ऋण स्थिरता सुनिश्चित की गई

पिछले दो वर्षों में निरंतर राजस्व सुधार

- ◆ 'सकल कर राजस्व' का आधा भाग प्रत्यक्ष कर है।
- ◆ वे राजस्व वृद्धि के प्रमुख चालक हैं।

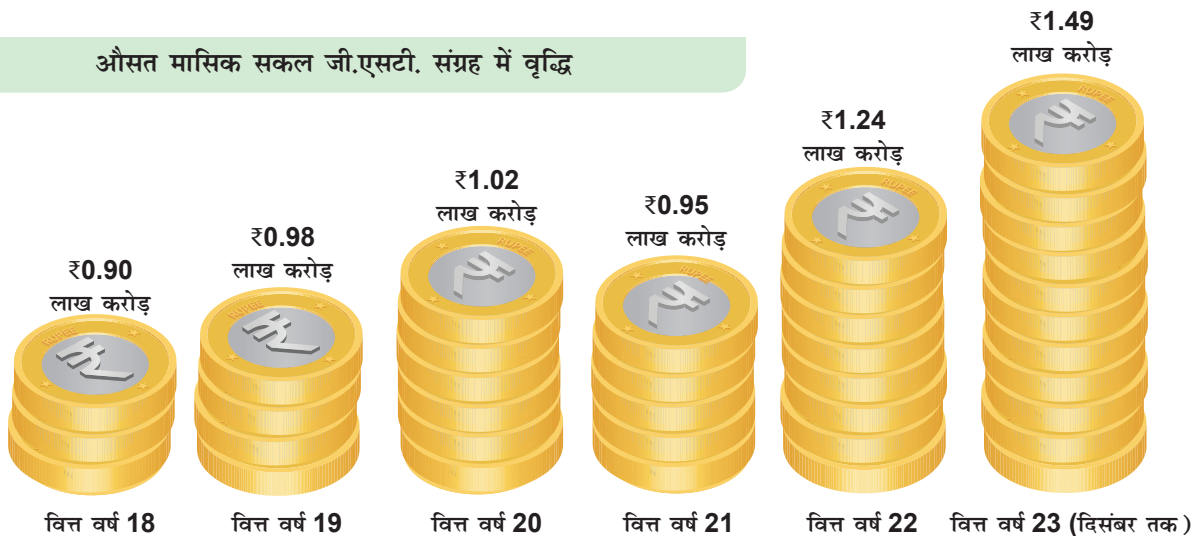


- ◆ अप्रैल-नवंबर 22 के लिए साल-दर-साल विकास दर लंबी अवधि के औसत से अधिक है



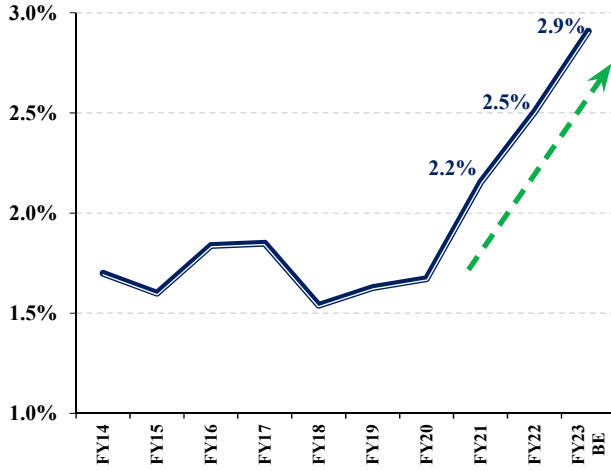
■ Apr-Nov 2022 ■ Avg FY2013-19 (Apr-Nov)

औसत मासिक सकल जी.एस.टी. संग्रह में वृद्धि

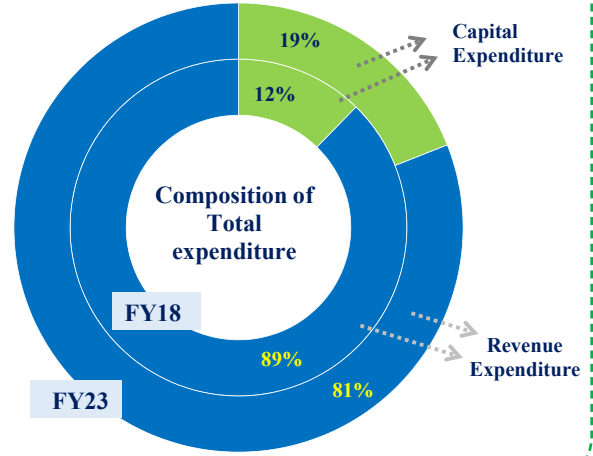


व्यावहारिक व्यय: पुनः प्राथमिकता

केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बढ़ रहा है।



केंद्र के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का बढ़ता हिस्सा



चुनिंदा क्षेत्रों में कैपेक्स (अप्रैल-नवंबर 22)



सड़क परिवहन और राजमार्ग
(₹1.5 लाख करोड़)



रेलवे
(₹1.5 लाख करोड़)



रक्षा सेवाएं
(₹0.7 लाख करोड़)



दूरसंचार
(₹0.3 लाख करोड़)

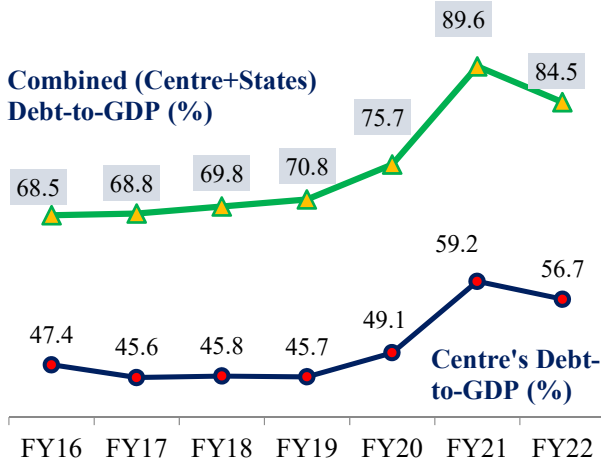
सहकारी राजकोषीय संघवाद

- ◆ महामारी के समय जीएसटी मुआवजे की सहायता करने के लिए राज्यों को केंद्र द्वारा दिया जाने वाला ऋण भविष्य के उपकर संग्रह के माध्यम से चुकाया जाएगा
- ◆ मुआवजा भुगतान और कर विचलन किशतों को असमान रूप से वितरित किया गया ताकि राज्यों को धन शीघ्र मिल सके
- ◆ राज्यों के लिए जीएसडीपी (वित्त वर्ष 21) का 5%, 4% (वित्त वर्ष 22) और 3.5% (वित्त वर्ष 23) के लिए बढ़ी हुई उधार सीमा; बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ी जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.5%
- ◆ उधार लेने में सशर्त घटक के माध्यम से सुधार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया गया।
- ◆ ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹1.05 लाख करोड़ के माध्यम से राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र की सहायता।

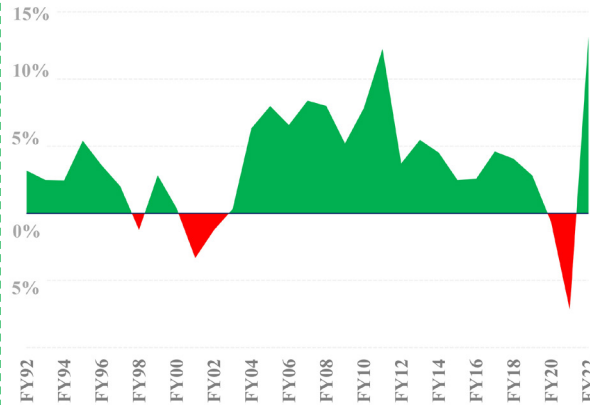
सरकारी ऋण स्थिरता चिंता का विषय नहीं है

महामारी वर्ष के दौरान चरम के बाद सरकारी ऋण को सामान्य करना

Combined (Centre+States) Debt-to-GDP (%)

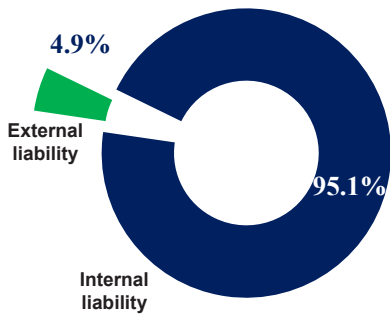


सकारात्मक विकास-ब्याज दर का अंतर सरकारी ऋण को नियंत्रित रखता है

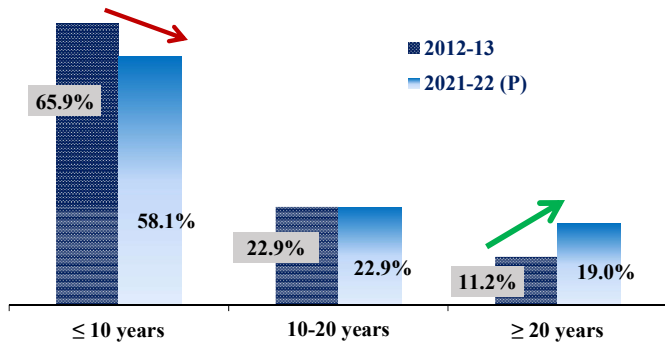


कम मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के साथ स्थिर सरकारी ऋण विवरण

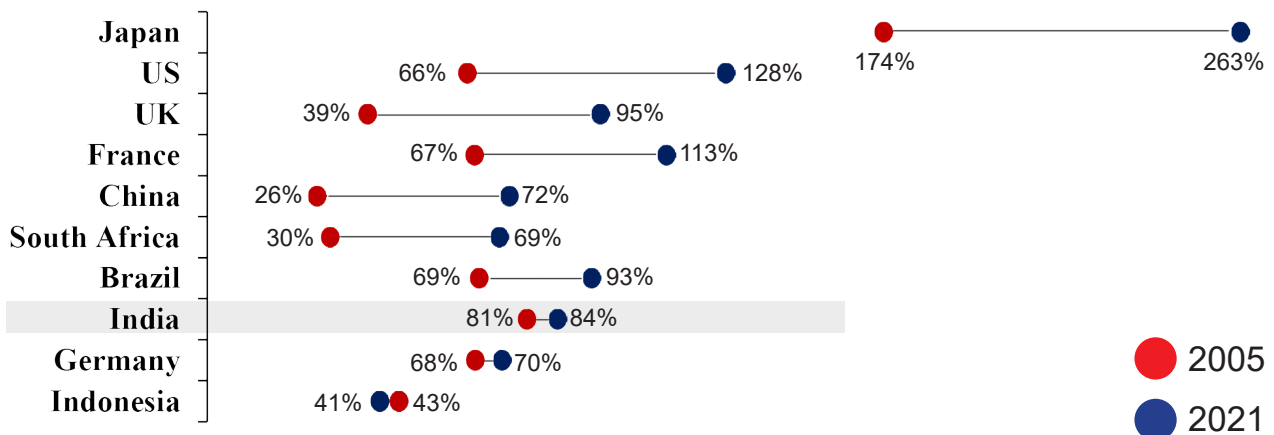
केंद्र सरकार के कर्ज में विदेशी देनदारियों का कम अनुपात



सरकारी ऋण परिपक्वता प्रोफाइल का विस्तार



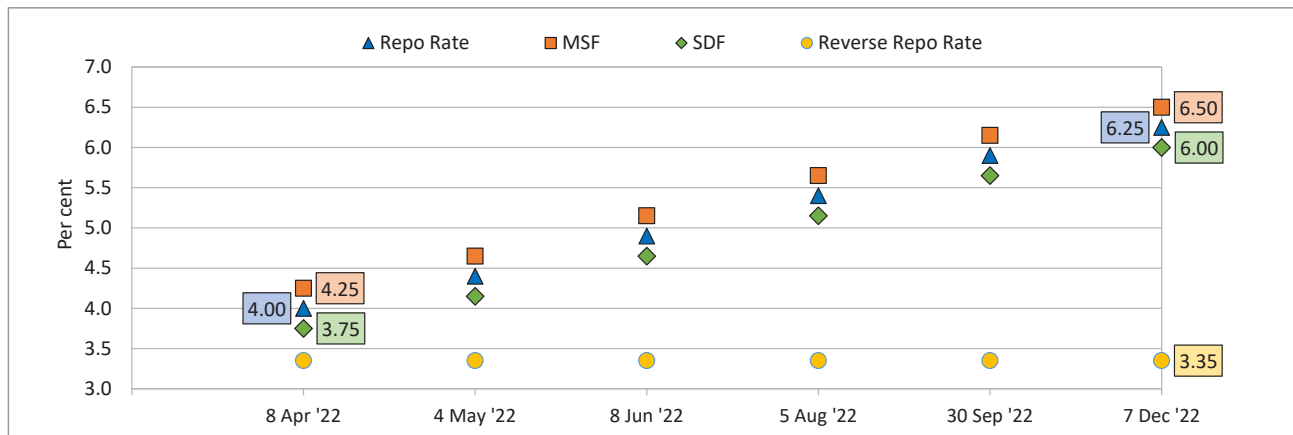
मित्र राष्ट्रों के सापेक्ष, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (%) और सरकारी ऋण में मामूली वृद्धि



Source : IMF

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: एक अच्छा वर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में संचयी 225 आधार अंको (bps) की वृद्धि की



रेपो रेट में बढ़ोतरी करने की मौद्रिक नीति जाती है।

WALR Fresh Rupee Loan
(Weighted Average Lending Rate)



April to November, 2022

135 bps



WADTDR Outstanding Deposit
(Weighted Average Domestic Term Deposit Rate)

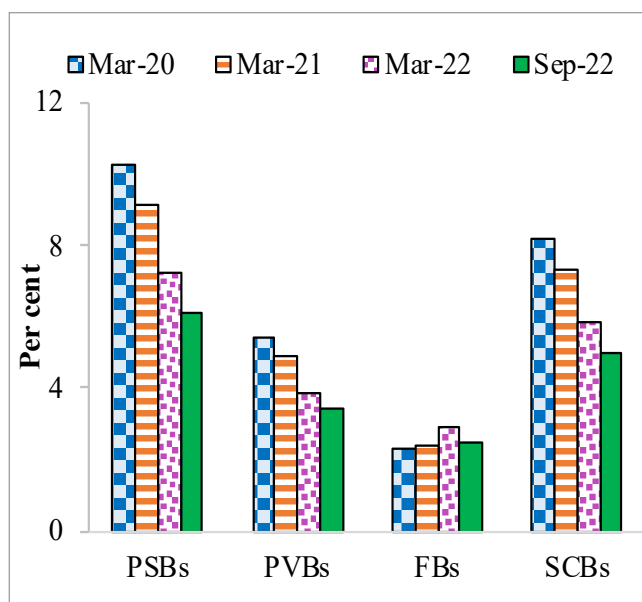


April to November, 2022

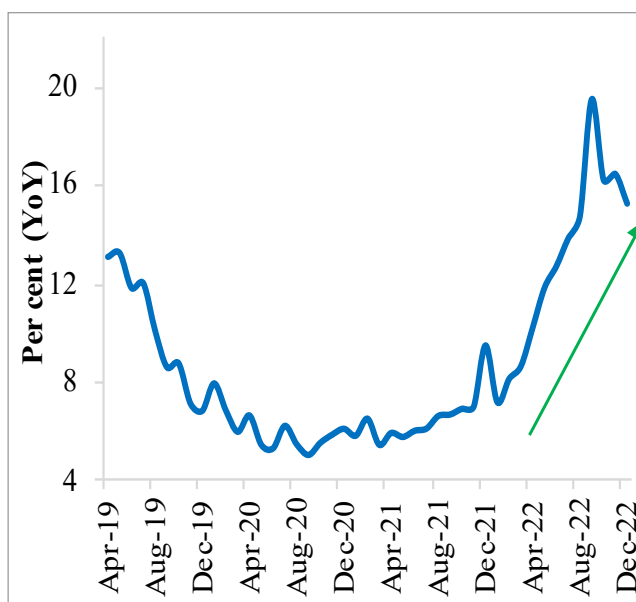
59 bps



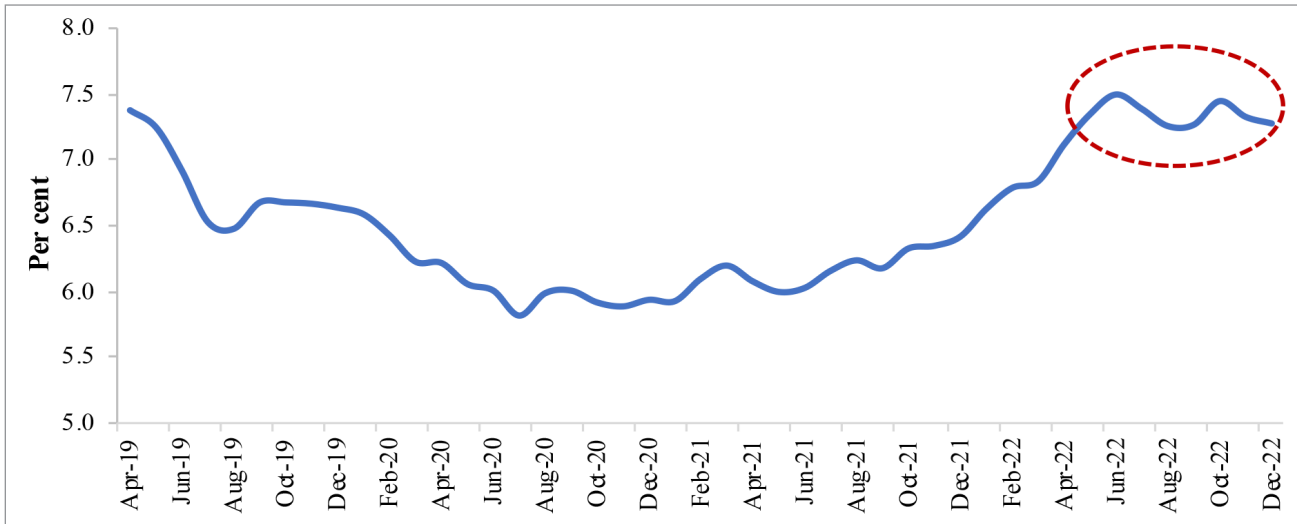
सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) अनुपात सात साल के निचले स्तर 5 प्रतिशत पर



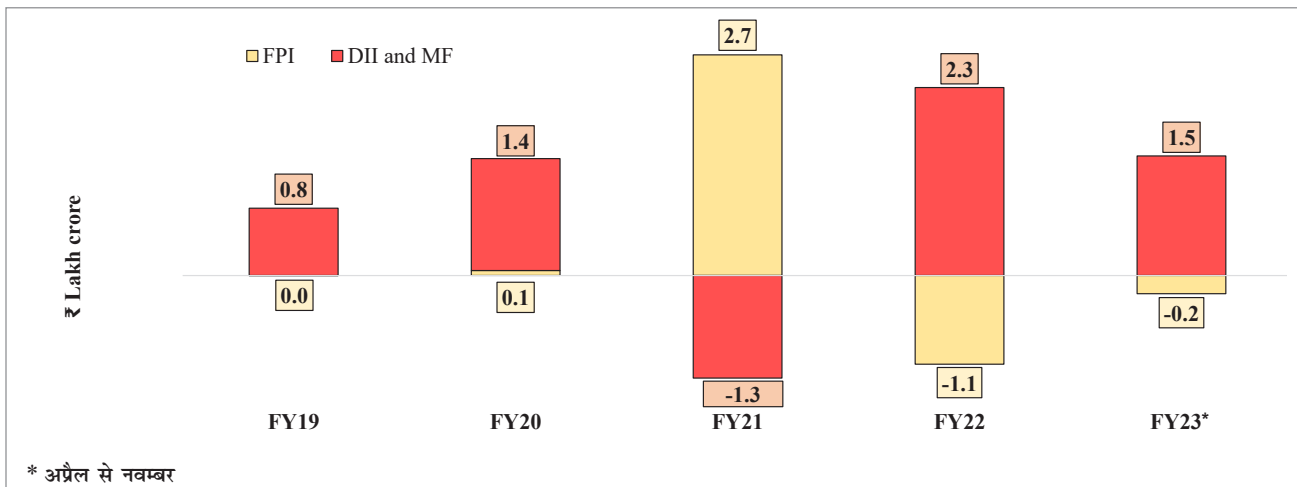
अप्रैल-22 से गैर-खाद्य ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में



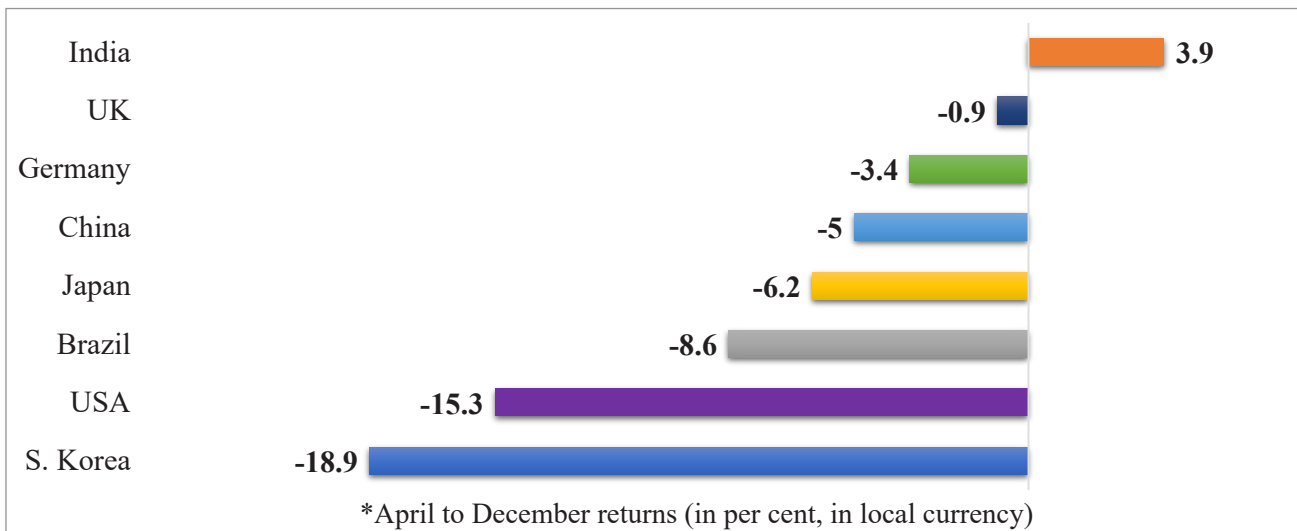
2022 में 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर स्थिर यील्ड



घरेलू संस्थागत निवेशकों ने हाल के वर्षों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्प्रवाह के लिए एक प्रतिकारी बल के रूप में कार्य किया



शेयर बाजार का प्रदर्शन: भारत ने वित्त वर्ष 23 में अपने मित्रों को पीछे छोड़ दिया *



स्रोत: ब्लूमबर्ग

कीमतें और मुद्रास्फीति: कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना

महंगाई चरम सीमा पर से लौट रही है

- सरकार के बहु-आयामी दृष्टिकोण के नेतृत्व में थोक मूल्यों में संतुलन के साथ-साथ वैश्विक पण्य की कीमतों में नरमी आई जबकि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट सब्जियों, फलों और खाद्य तेल के कारण हुई।
- सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच की दूरी 21 नवंबर और 22 मई को आधार प्रभावों के लुप्त होने और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण पण्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण क्रमशः कीमत बढ़ गई। बाद में निम्नलिखित के कारण अभिसरण देखा गया:

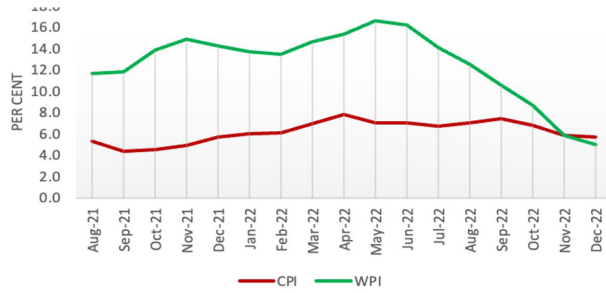


थोक मूल्य सूचकांक (जैसे लोहा, एल्युमीनियम और कपास) में जिन वस्तुओं का अधिक भार था, उनकी कीमतों में गिरावट

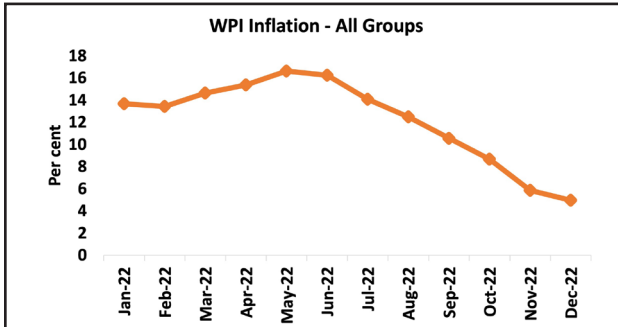


सीपीआई बास्केट पर सेवाओं की मुद्रास्फीति की निरंतरता (जैसा कि सीपीआई कोर मुद्रास्फीति में देखा जा सकता है)

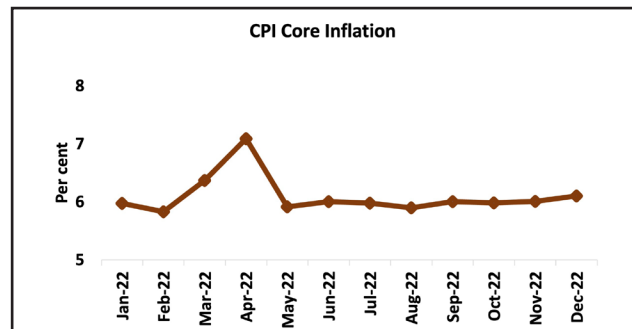
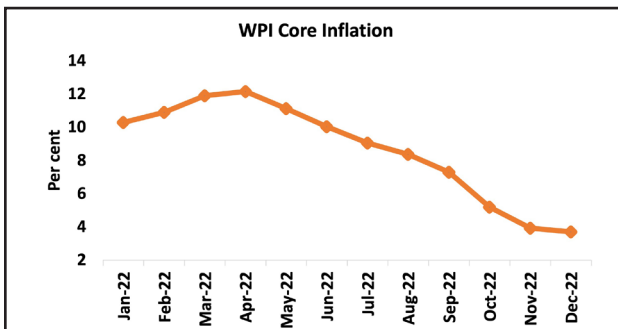
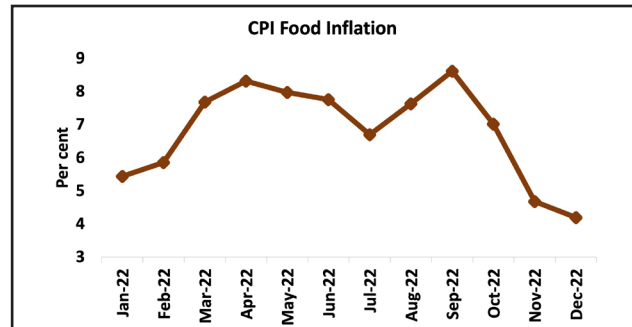
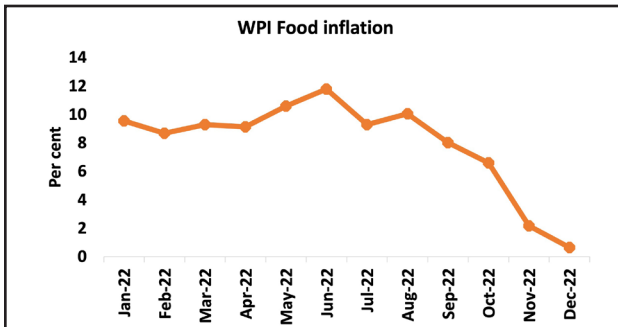
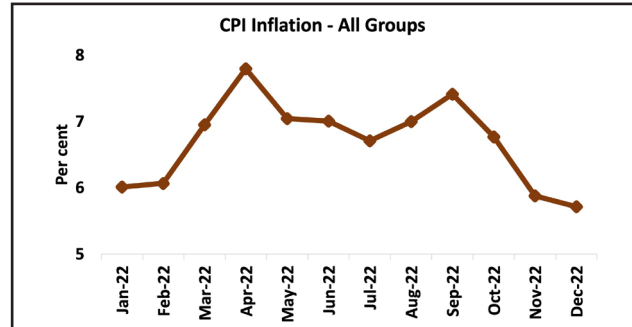
सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच अभिसरण



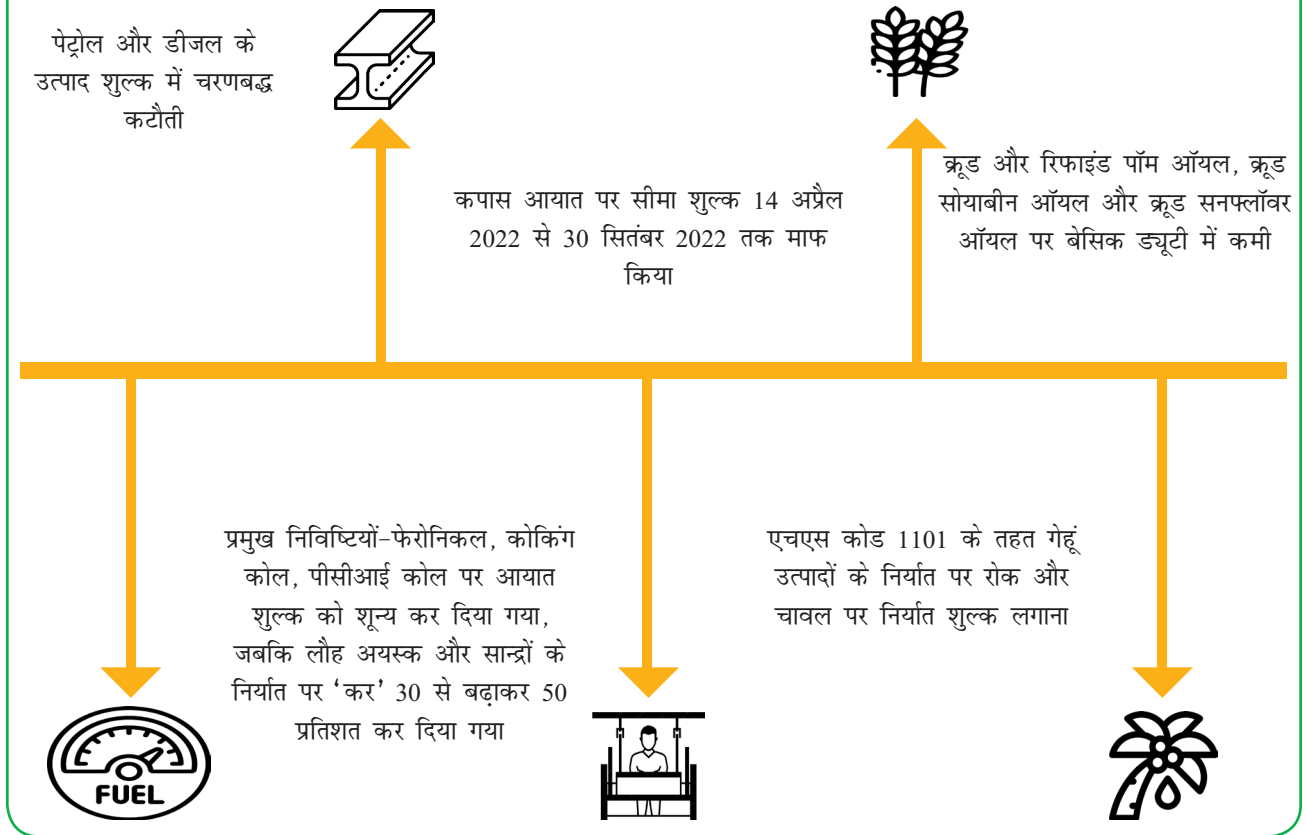
प्रमुख खंड: थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति



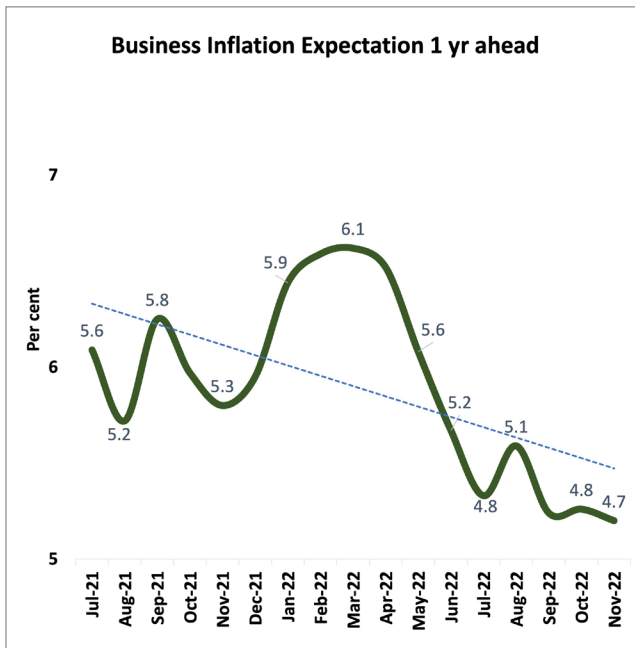
प्रमुख खंड: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति



महंगाई रोकने के सरकारी उपाय

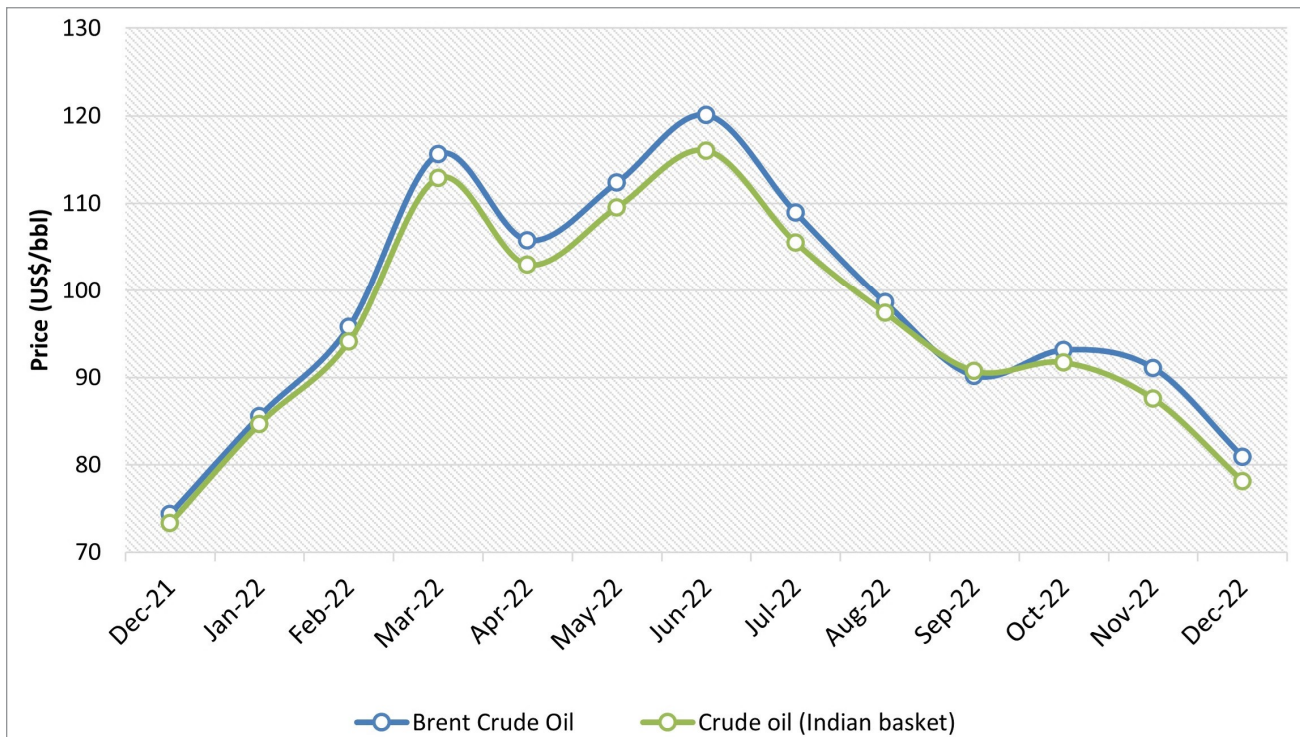
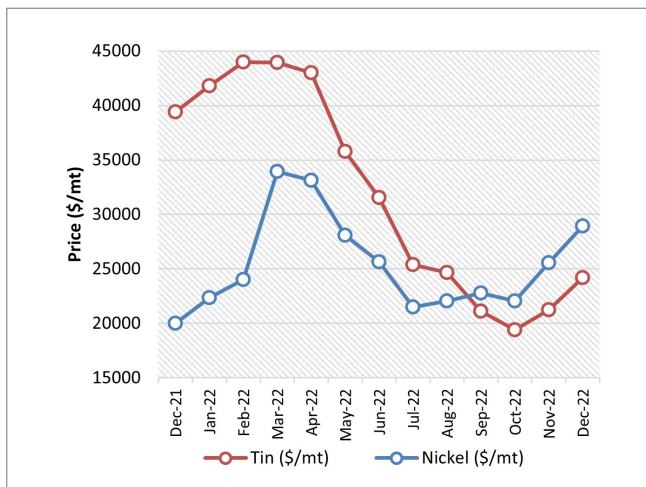
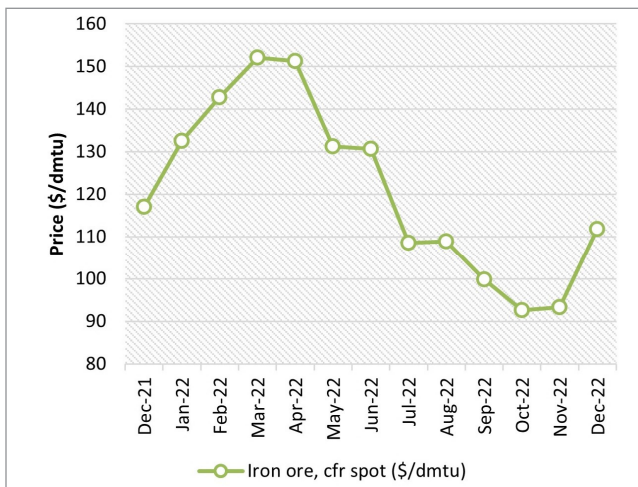
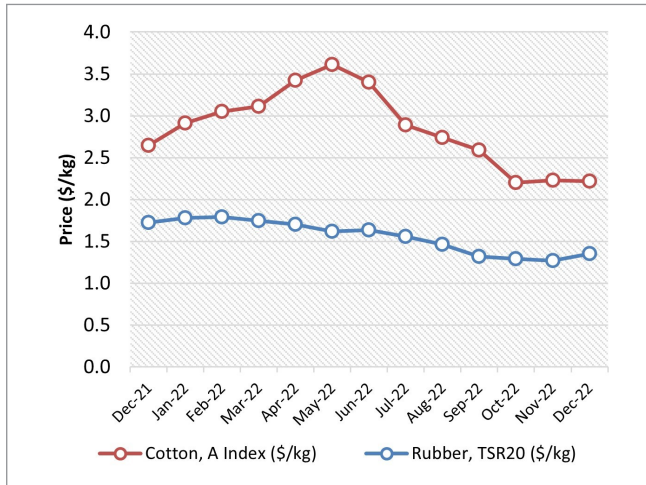
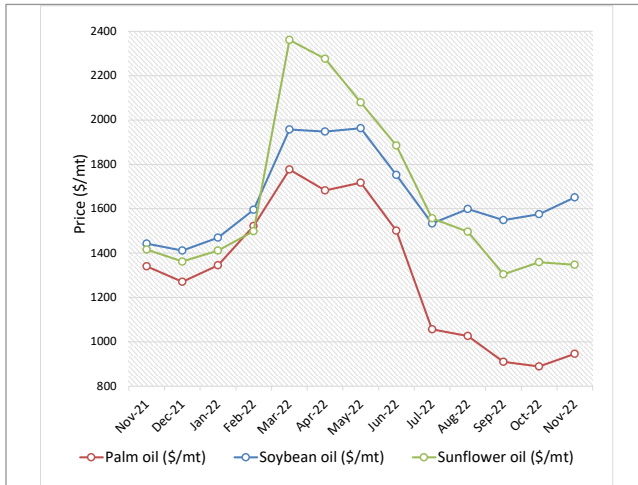


मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को कम करना

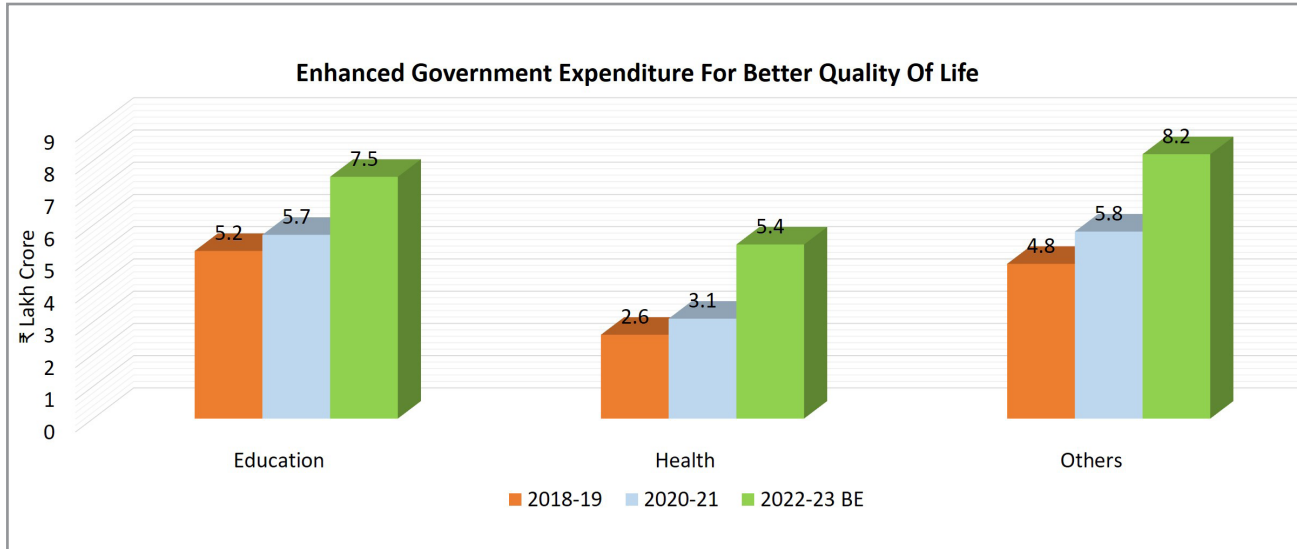


स्रोत: आई.आई.एम. अहमदाबाद और भारतीय रिजर्व बैंक

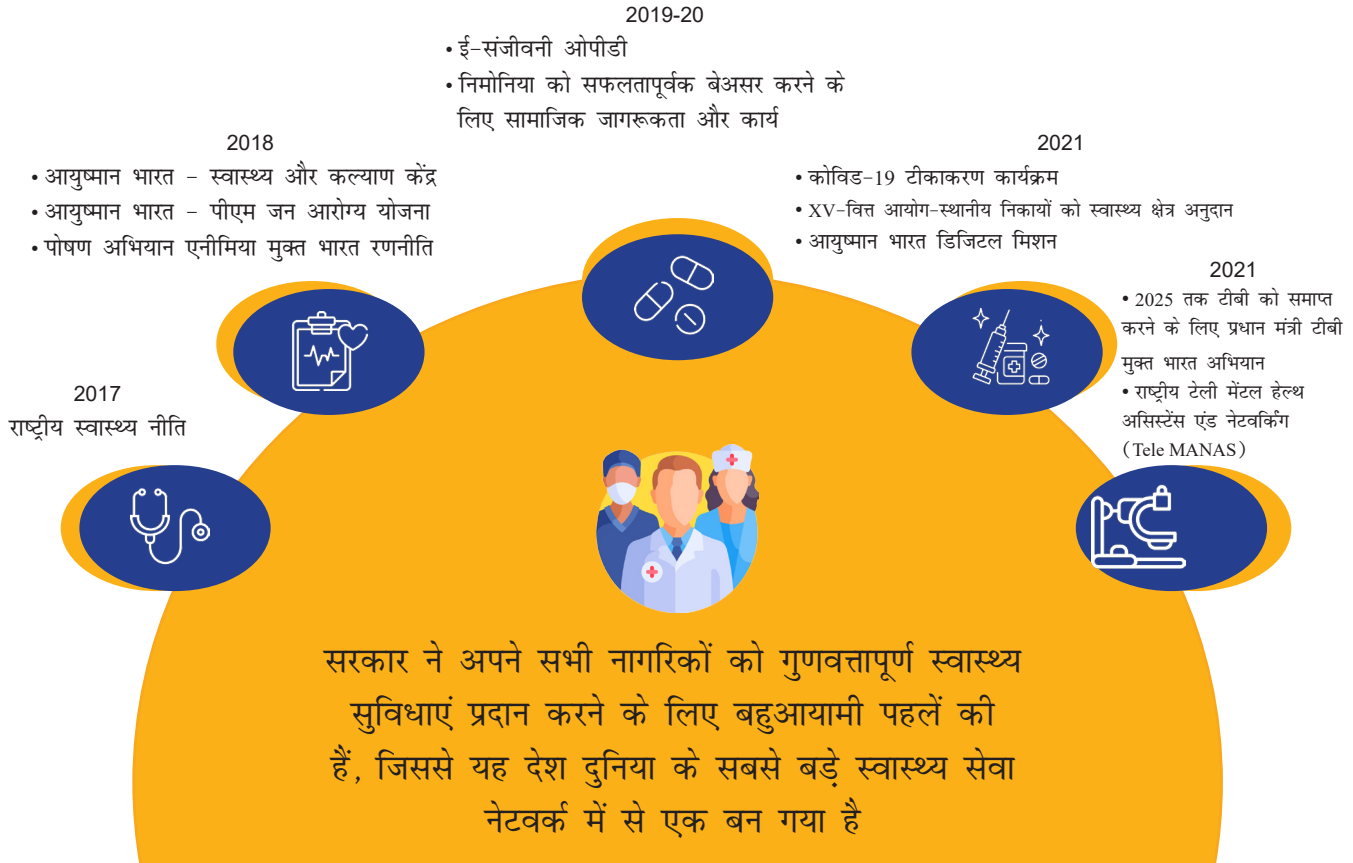
वैश्विक पण्य वस्तुओं में किफ़ायत



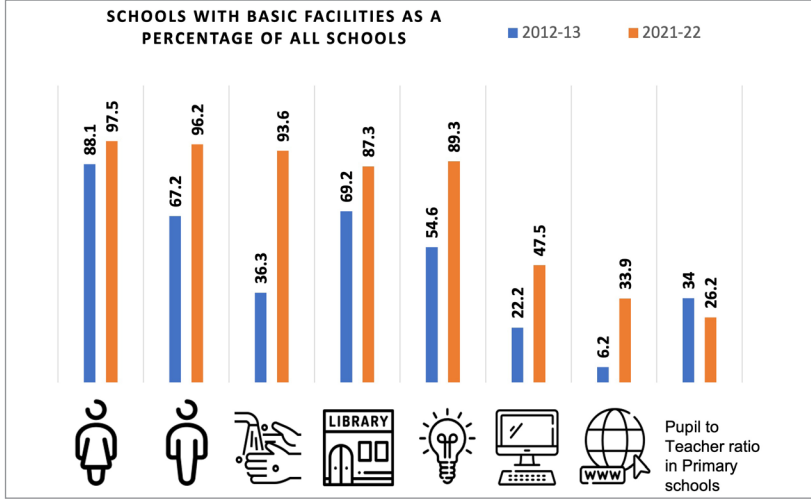
सामाजिक अवसंरचना और रोजगार: व्यापक व्यवस्था



सभी के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य



स्कूल की बुनियादी सुविधाओं में सुधार



शिक्षा के लिए पहल

- वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 27 के बीच 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा में परिवर्तन
- आईआईटी की संख्या में 16 से 23, आईआईएम की संख्या 13 से 20, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से 648, आईआईआईटी की संख्या 9 से 25 हुई

जीवन में गुणवत्ता में सुधार के लिए विशाल शिविर व्यापक सहयोग

22 करोड़ (एबी-पीएमजेएवाई) लाभार्थी

पीएमएवाई-जी के तहत
2.1 करोड़ घरों का
निर्माण

सभी के लिए
आवास



किफायती और
कुशल स्वास्थ्य
सेवा



पीएमजीएसवाई के तहत
2000 से अब तक 7.2 लाख
किलोमीटर सड़कों का निर्माण
बारहमासी सड़कें

बारहमासी सड़कें



सौभाग्य के तहत 2.9
करोड़ ग्रामीण घरों का
विद्युतीकरण किया गया

विद्युत आपूर्ति



जीवन की गुणवत्ता

सामाजिक
सुरक्षा



प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन
में 49 लाख नामांकन,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
में 30 करोड़ नामांकन



स्वच्छता और
पेयजल

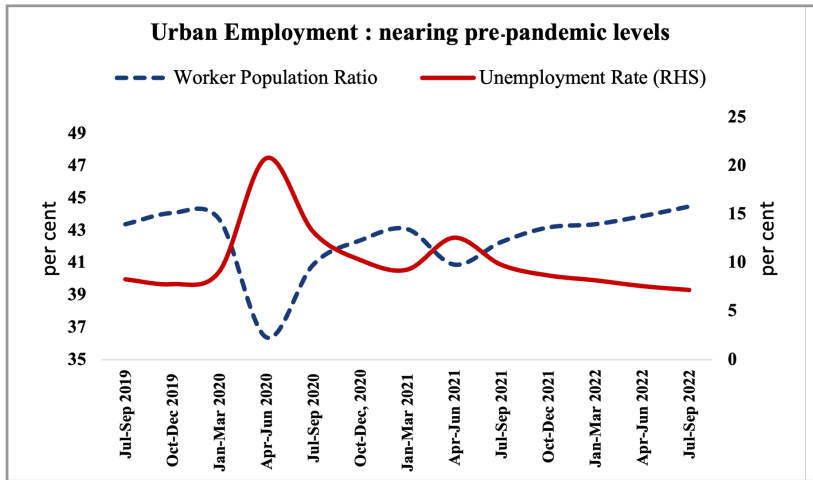
जेजेएम के तहत 11 करोड़ नल जल
कनेक्शन



भोजन पकाने का
स्वच्छ ईंधन

पीएमयूवाई के तहत 11 करोड़ एलपीजी
कनेक्शन दिए गए

रोजगार के लिए अधिक रास्ते और फॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में सुधार



आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से फॉर्मलाइजेशन में सुधार हुआ



सभी उद्योगों के लिए ईपीएफओ आधारित नेट पेरोल बढ़ रहा है: वित्त वर्ष 2020 में 78.6 लाख के मुकाबले वित्त वर्ष 23 (नवंबर तक) में 105.4 लाख

एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बना रहा है



वित्त वर्ष 20 में महिला एसएचजी की संख्या 88.3 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 1 करोड़ से अधिक हो गई



वित्त वर्ष 20 में सभी महिला एसएचजी से बचत ₹23,320.6 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में ₹42,104.8 करोड़ हो गई

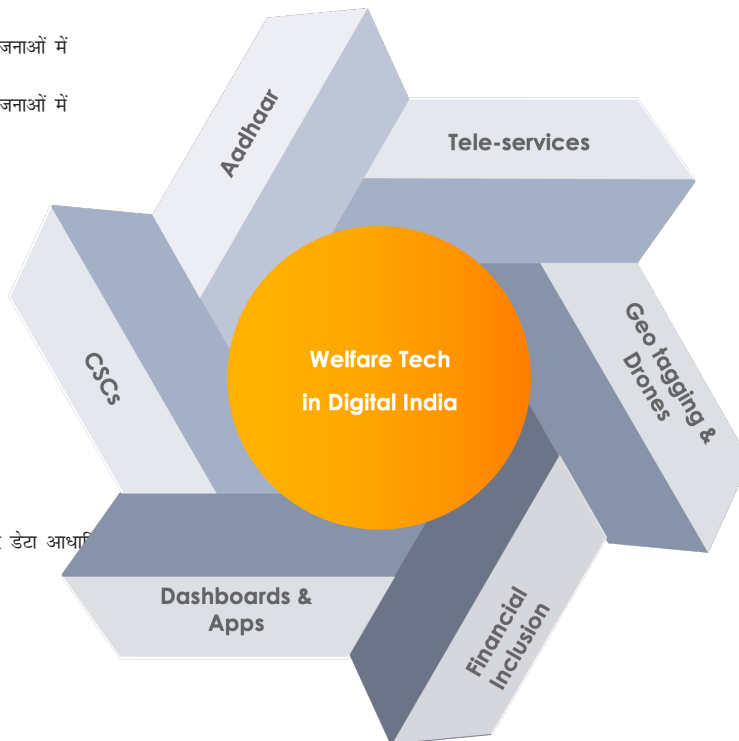
दरवाजे तक डिजिटल सेवाएं प्रदान करना

- 134 करोड़ यूनिट आईडी सृजित
- लगभग 900 केंद्रीय और राज्य योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- लगभग 900 केंद्रीय और राज्य योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

- प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर

निम्नलिखित के माध्यम से त्वरित और डेटा आधारित नीति बनाना:

- को-विन,
- ई-श्रम पोर्टल
- उमंग ऐप
- ई-श्रम पोर्टल
- आकांक्षी जिले और ब्लॉक
- जल जीवन मिशन



सेवाएं तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध हैं

- 9.3 करोड़ ई-संजीवनी टेली-परामर्श
- दीक्षा पोर्टल में 517 करोड़ सीखने के सत्र पोर्टल

शक्ति कुशल कार्यान्वयन:

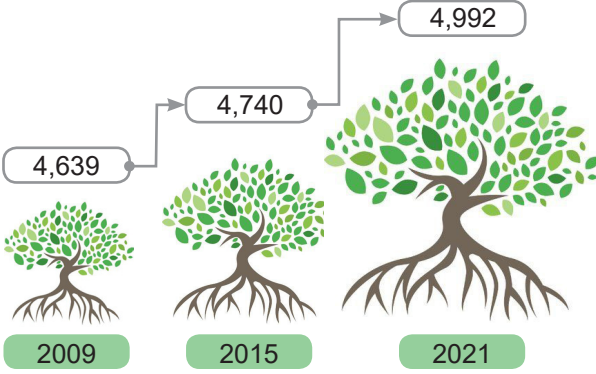
- 5.2 करोड़ मनरेगा संपत्तियों और 7.7 लाख ग्रामीण सुविधाओं की जियो-टैगिंग
- स्वामित्व के तहत 2.1 लाख गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण

- 56% महिला खाताधारकों के साथ 46 करोड़ जन-धन खाते

- डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 8.7 करोड़ महिलाएं एसएचजी में शामिल हुईं

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण: भविष्य का सामना करने की तैयारी

मैंग्रोव के तहत क्षेत्र का विस्तार (वर्ग किमी)



मौजूदा एनडीसी का अपडेट



2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करना



2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता



'लाइफ' - 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' के लिए एक जन आंदोलन



सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क (एसजीआरबीएस) नवंबर 2022 में जारी किया गया।



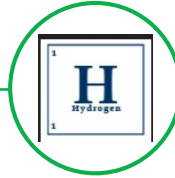
आरबीआई ने रुपए 4,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबीएस) के दो हिस्सों की नीलामी की।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मुख्य विशेषताएं



2030 तक संभावित परिणाम

- ▶ प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता।
- ▶ जीवाश्म ईंधन के आयात में संचयी कमी रुपए 1 लाख करोड़ से अधिक और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन।
- ▶ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी।



हस्तक्षेप

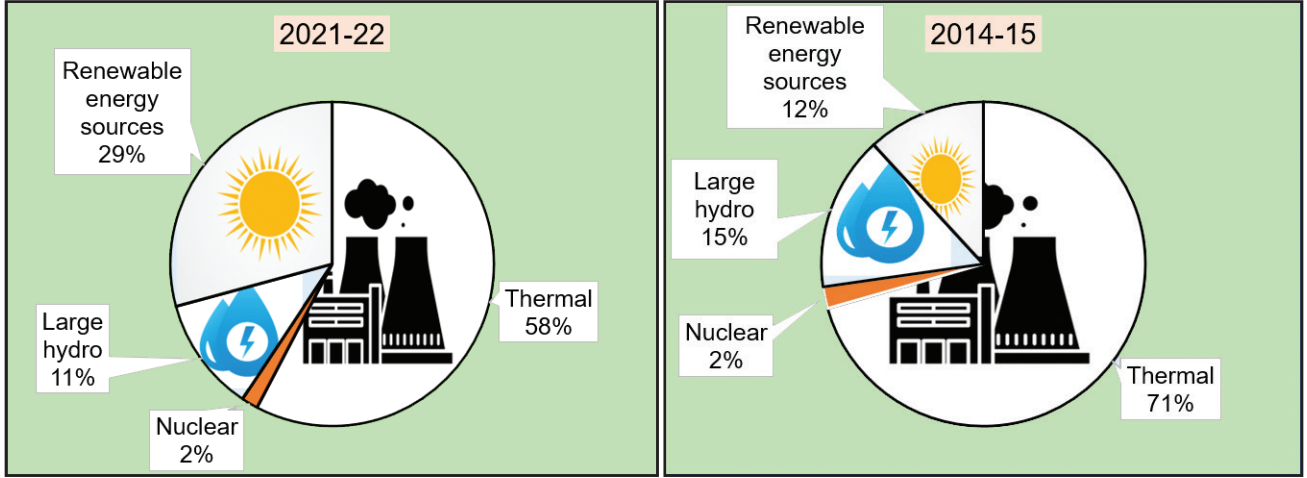
- ▶ इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन।
- ▶ बड़े पैमाने पर उत्पादन और/या हाइड्रोजन के उपयोग को ग्रीन हाइड्रोजन केंद्रों के रूप में विकसित करने में सक्षम क्षेत्र।



नीतिगत ढांचा

- ▶ ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक सक्षम नीतिगत ढांचे का विकास।
- ▶ मजबूत मानक और विनियम ढांचा।
- ▶ अनुसंधान एवं विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचा।
- ▶ कौशल विकास कार्यक्रम

स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों का बढ़ता हिस्सा



राष्ट्रीय सौर मिशन

- राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा क्षमता 61.6 ग्राम स्थापित (अक्टूबर 2022)



सस्टेनेबल हैबिट पर राष्ट्रीय मिशन।

- राष्ट्रीय स्थायी आवास मिशन 721 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क को 18 शहरों में परिचालित किया गया है।
- 62.8 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 6.2 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (अगस्त 2022)।



हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन

- इंटर-यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम
- 8 प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरू किए गए।



बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन

- 6.6 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) (अक्टूबर 2021) के ऊर्जा बचत लक्ष्य के लिए पीएटी चक्र-VII अधिसूचित

जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन

जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 8 मिशनों की प्रगति



राष्ट्रीय जल मिशन

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन 2022' (मार्च 2022 में लॉन्च किया गया।)



जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

- जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए और मजबूत किए गए (जून 2021)।



ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन

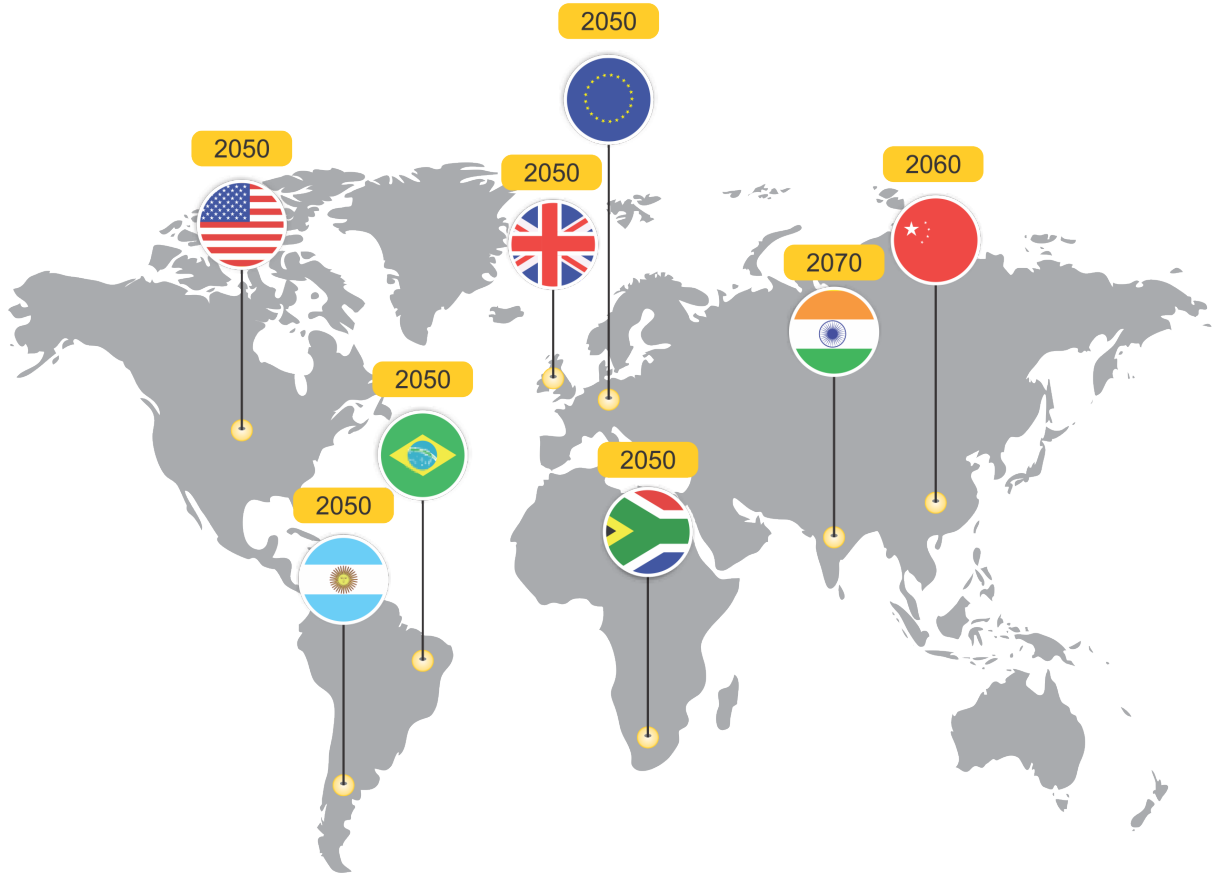
- 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण लक्ष्य के लिए 626.9 करोड़ रुपये।



स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन

- जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाले प्रमुख लक्ष्य।

नेट जीरो प्लेड्ज



यू.एस



अर्जेन्टिना



ब्राजील



यूरोप



दक्षिण अफ्रीका



भारत



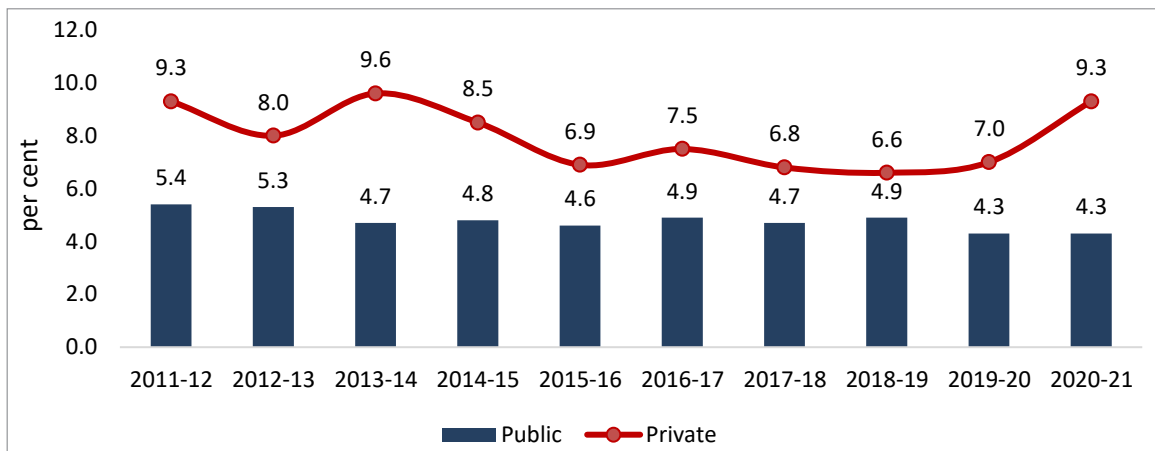
चीन



यू.के

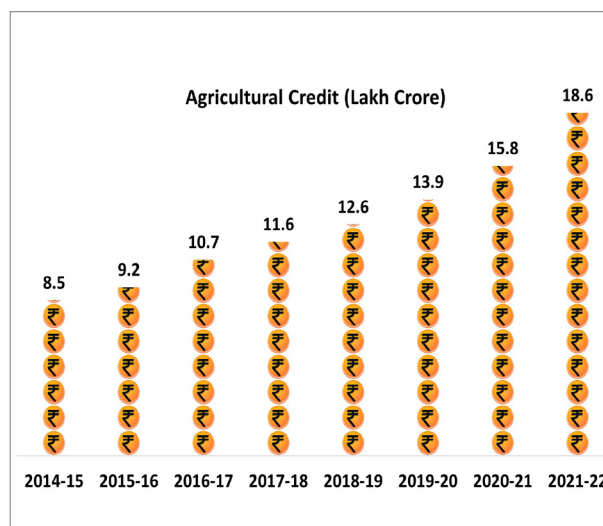
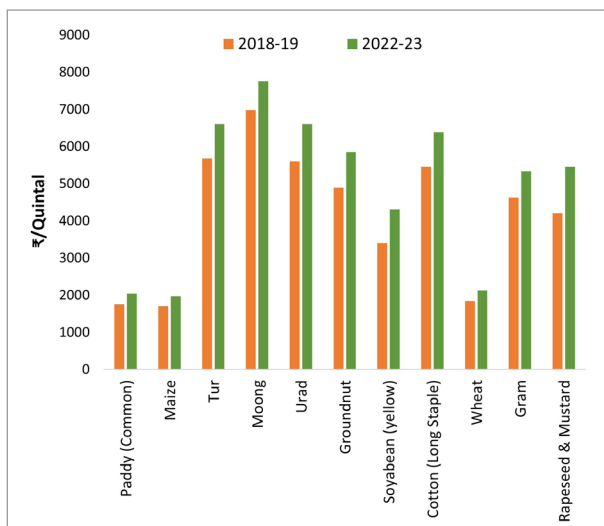
कृषि और खाद्य प्रबंधन: खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक

कृषि क्षेत्र में निजी निवेशकों की भीड़

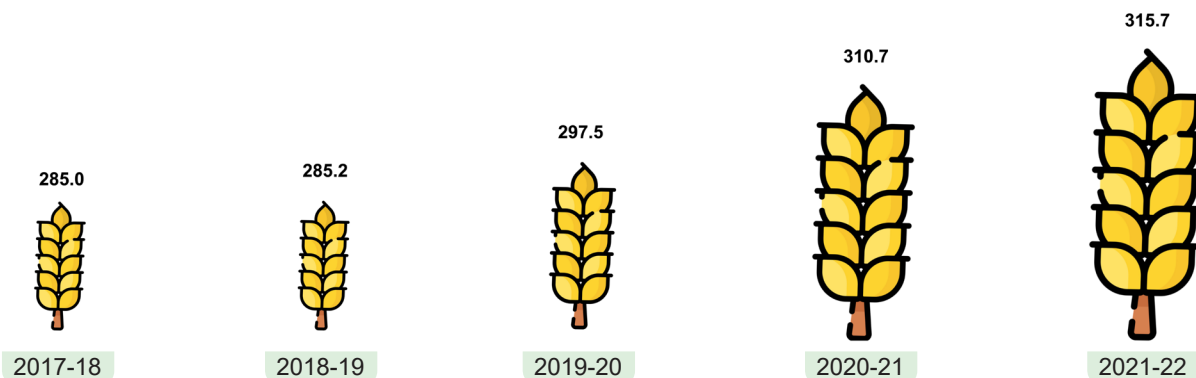


2018 से, सभी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी अखिल भारतीय भास्ति औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय किया गया है।

कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि



भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि (मिलियन टन)

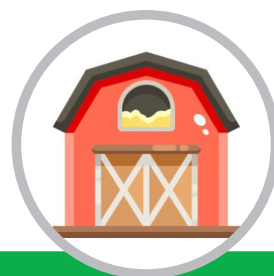


कृषि में महत्वपूर्ण पहल



पीएम-किसान

स्थापना के बाद से वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हुए 11.3 करोड़ किसानों को शामिल किया गया



कृषि अवसंरचना कोष

13,681 करोड़ रुपये की मंजूरी के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट और कम्युनिटी फार्म



पीएम-फसल बीमा योजना

दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना, जिसके शुरुआत से ही किसानों को 1.2 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा मिल रहा है



बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन

भौगोलिक विशेषज्ञताओं का लाभ उठाना



राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना

1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों के साथ ऑनलाइन, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी बोली प्रणाली



आर्गेनिक फार्मिंग

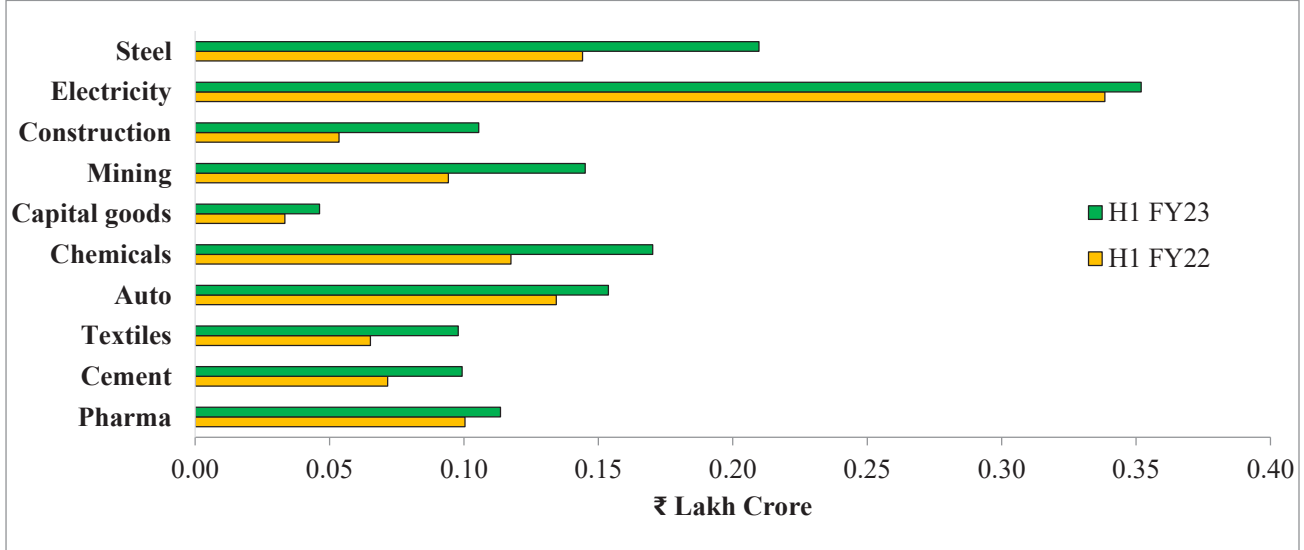
परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है

मिलेट(बाजरा) का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष: हमारा पारंपरिक स्टेपल और एक स्वास्थ्यप्रद विकल्प



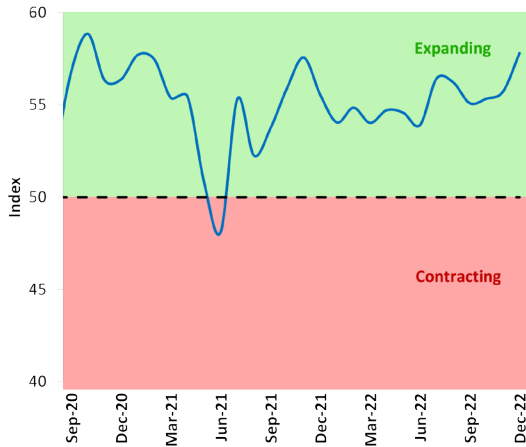
उद्योग: स्थिर वसूली

विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ता निजी निवेश

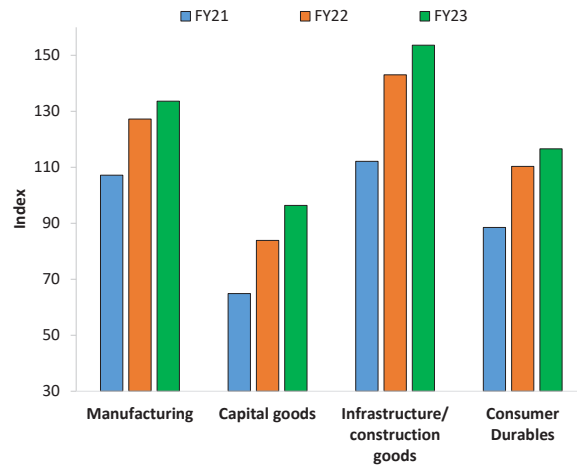


स्रोत: एक्सिस बैंक रिसर्च, कैपिटल लाइन

विस्तार क्षेत्र में पीएमआई विनिर्माण



आईआईपी स्वस्थ गति से बढ़ रहा है (अप्रैल-नवंबर)



एमएसएमई द्वारा संचालित उद्योग में क्रेडिट वृद्धि

एमएसएमई को क्रेडिट



21 दिसंबर से एमएसएमई को क्रेडिट ग्रोथ लगभग 30%

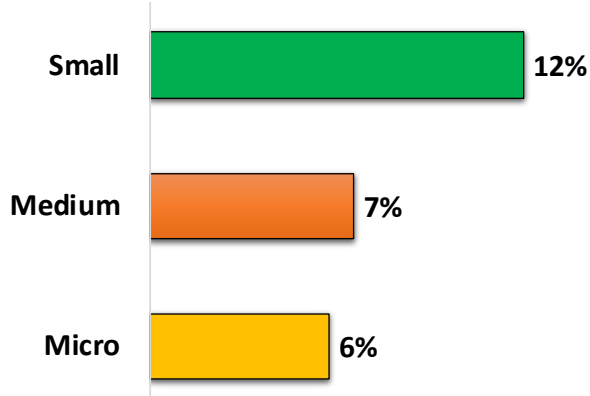
बड़े उद्योग को क्रेडिट



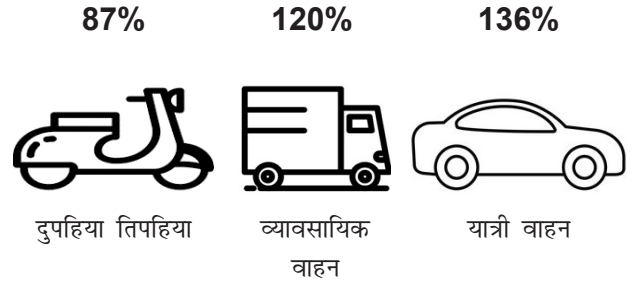
22 अक्टूबर से दो अंकों की वृद्धि

क्षेत्रीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में एमएसएमई द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी में वृद्धि

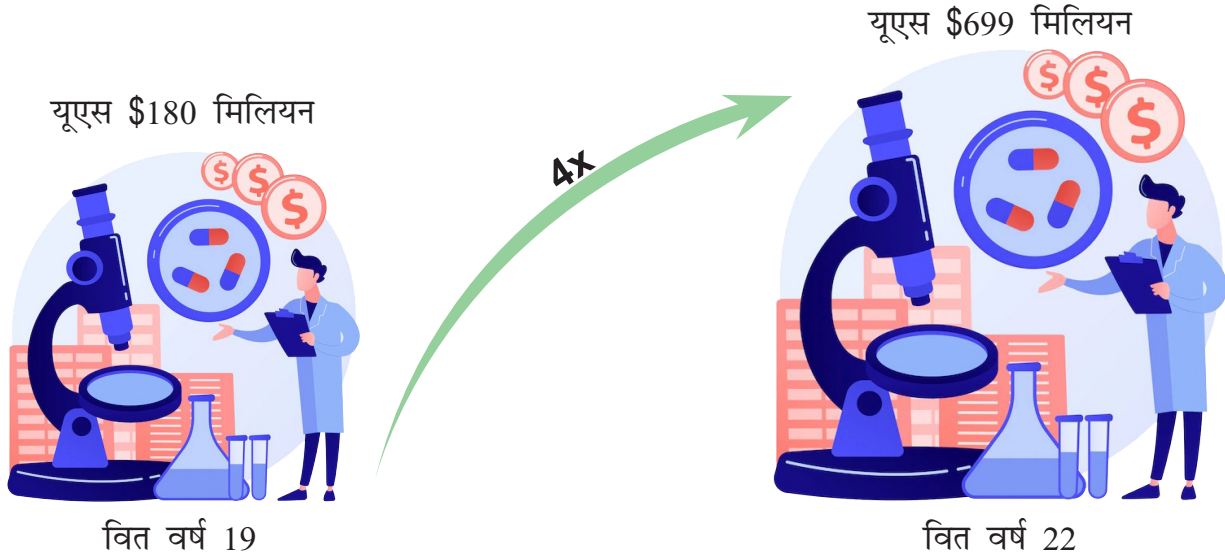


वित्त वर्ष 23 ' में स्मार्ट रिकवरी के बाद ऑटोमोबाइल बिक्री (दिसंबर 2022 तक)



* Recovery from pre-pandemic sales level of FY20.

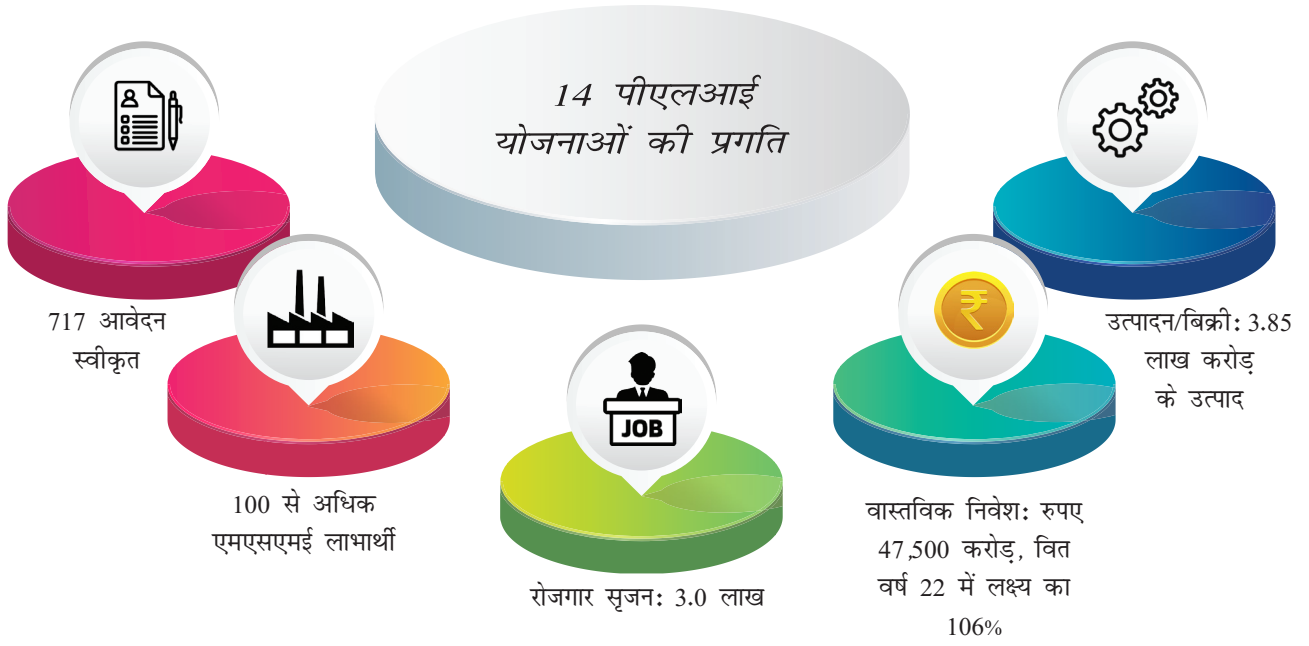
फार्मा उद्योग में एफडीआई फ्लो



इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 3 गुना बढ़ा



विनिर्माण क्षमता में वृद्धि



ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना

- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (पांचवें संस्करण) के 2020 के आकलन से पता चलता है कि राज्यों और संघशासित प्रदेशों में 7,496 सुधार लागू किए गए थे।
- 39,000' से अधिक अनुपालन कम किए गए
- 3,500' से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया

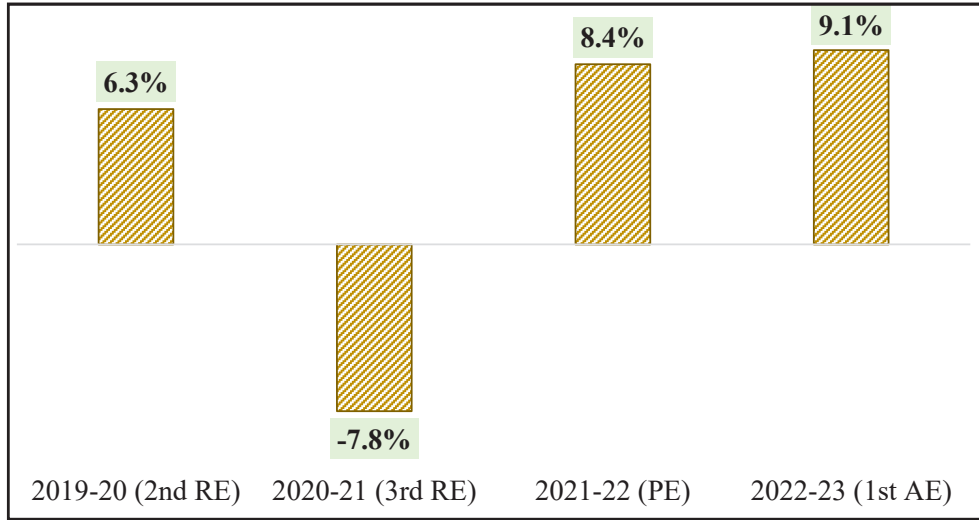
*17 जनवरी 2023 तक

मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 24 उप-क्षेत्र

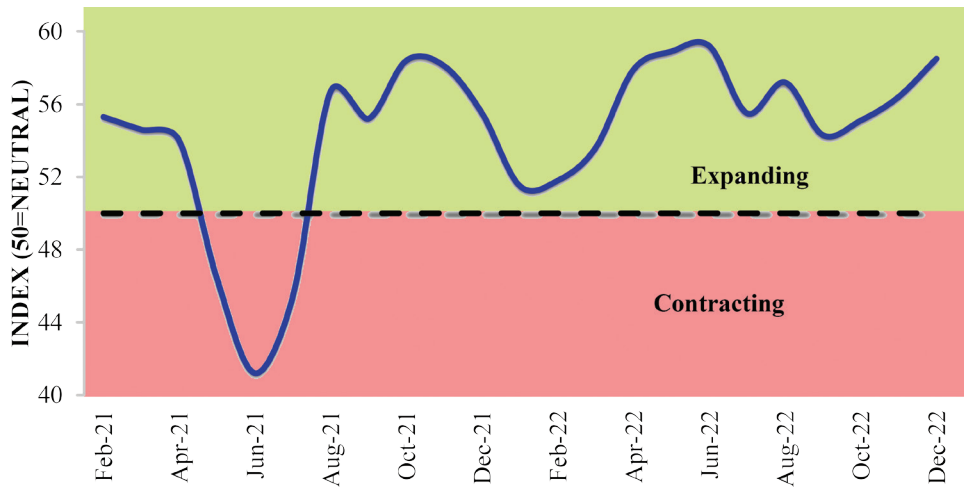


सेवाएं: क्षमता के स्रोत

सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 23 में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी

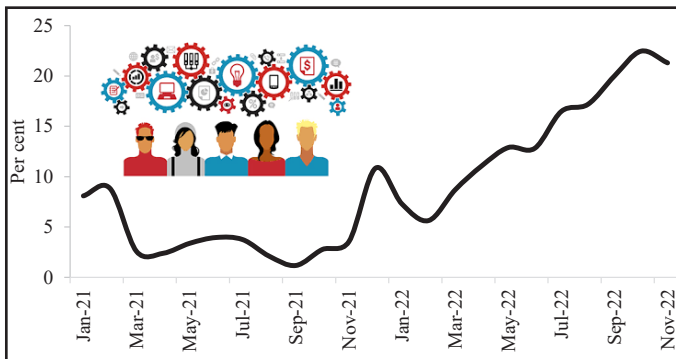


जुलाई 22 से पीएमआई सेवाओं ने सबसे महत्वपूर्ण विस्तारण देखा



‘क्रेडिट ग्रोथ’ से सेवा क्षेत्र में व्यापक आधार वृद्धि

क्रेडिट से सर्विस



जुलाई 22 से 16% से ऊपर क्रेडिट वृद्धि से सर्विस

क्रेडिट से व्यापार क्षेत्र

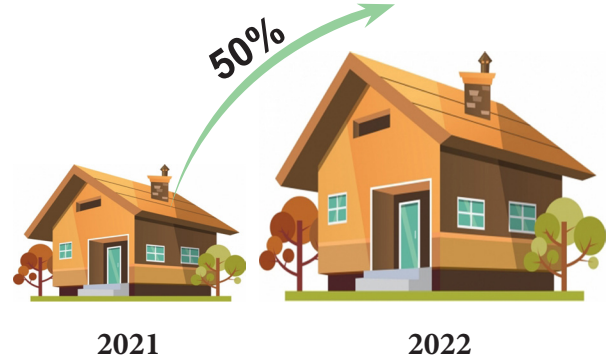
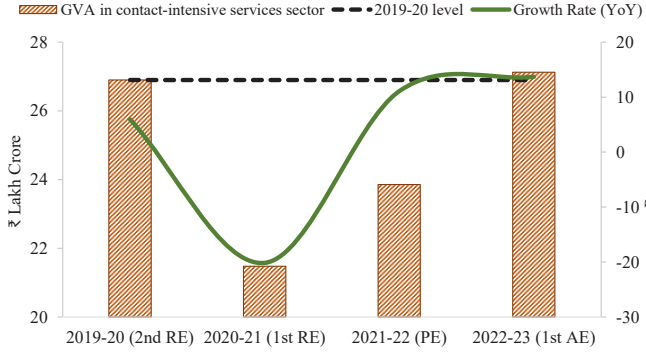


अप्रैल 22 से द्वि-अंकीय वृद्धि (13% से ऊपर)

क्षेत्रीय निष्पादन

वित्त वर्ष में पूर्व-महामारी स्तर पुनः प्राप्त करने के लिए संपर्क-गहन सेवाएं

पूर्व-महामारी स्तर पुनः प्राप्त करने के लिए मकान विक्रय में संधारणीय वृद्धि



स्रोत: प्रोजेक्ट टाईगर

होटल के अधिभोग दर में सुधार

भारत की वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करते डिजिटल प्लेटफार्म

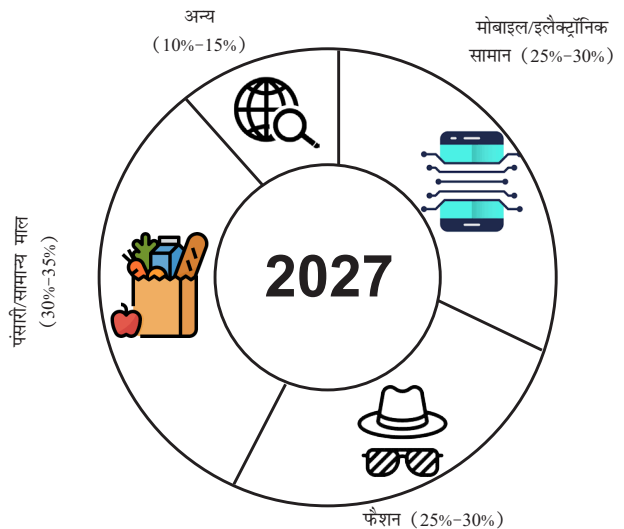
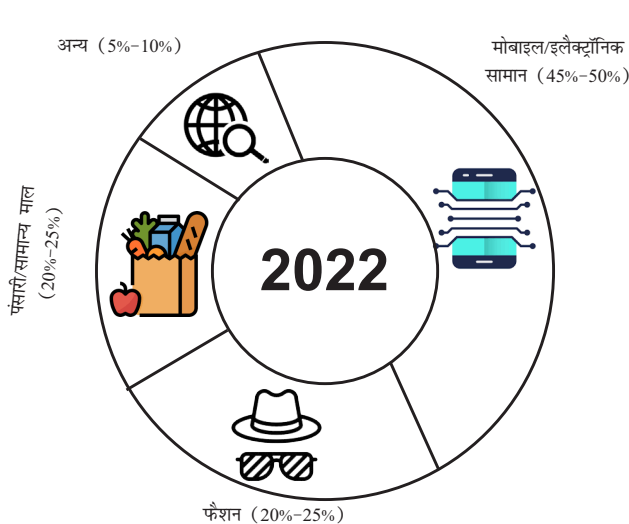


स्रोत: एनारोक

75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की घोषणा



2027 तक भारतीय ई-वाणिज्य बाजार की लगभग दो-तिहाई प्राप्ति के लिए फैशन, पंसारी और सामान्य माल



स्रोत: भारत कैसे ऑनलाइन खरीदारी करता है, बेन और कंपनी

वैदेशिक क्षेत्र: सतर्क और आशावादी

भारत का बढ़ता और विविधतापूर्ण माल व्यापार

अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान यूएस \$305.0 बिलियन की अपेक्षा अप्रैल-दिसंबर 2022 के लिए माल निर्यात यूएस \$332.8 था

विविधतापूर्ण बाजार निर्यात भाग में वृद्धि



वित्त वर्ष 19 वित्त वर्ष 23*
1.2 **2.5**

ब्राजील



वित्त वर्ष 19 वित्त वर्ष 23*
1.2 **2.0**

दक्षिण अफ्रिका

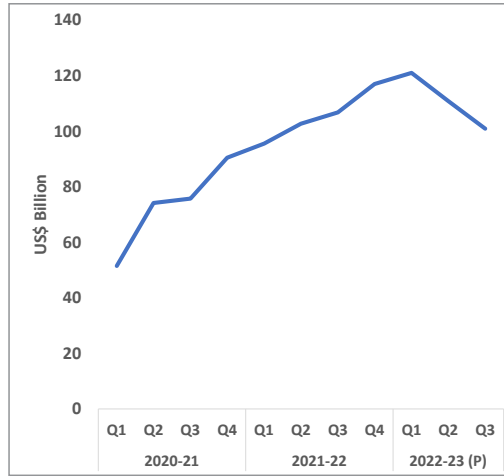


वित्त वर्ष 19 वित्त वर्ष 23*
1.7 **2.3**

सऊदी अरब

* अप्रैल-नवम्बर

लचीला माल निर्यात



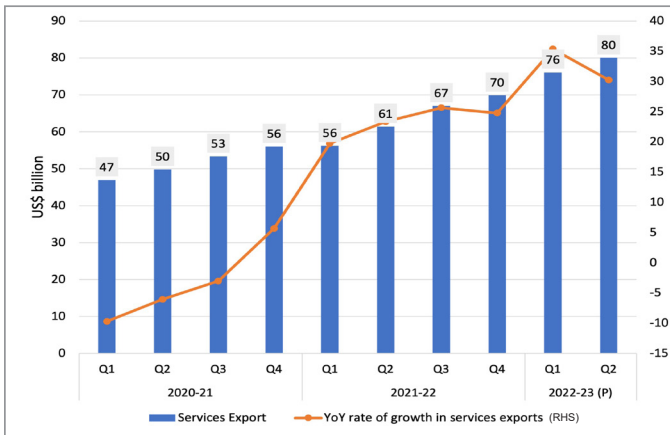
बाजार के आकार में वृद्धि

13 मुक्त व्यापार करार 6 वरीयता व्यापार लागू करार

हालिया एफ.टी.ए.

- हालिया एफटीए भारत-यूई का व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीडीपीए) 1 मई 2022 को लागू हुआ।
- भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार (भारत-आस्ट्रेलिया ईसीटीए), 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ

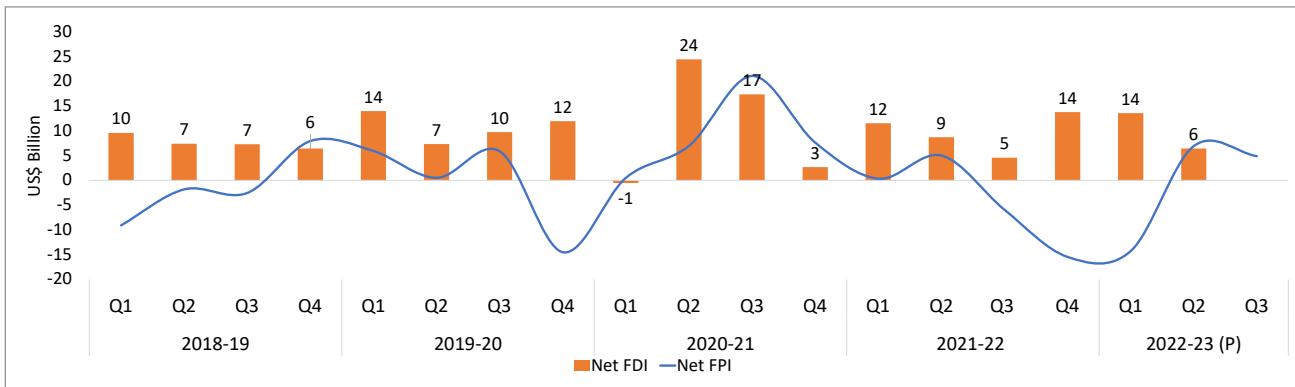
व्यापार संतुलन को सुरक्षा देते सुदृढ़ सेवा निर्यात



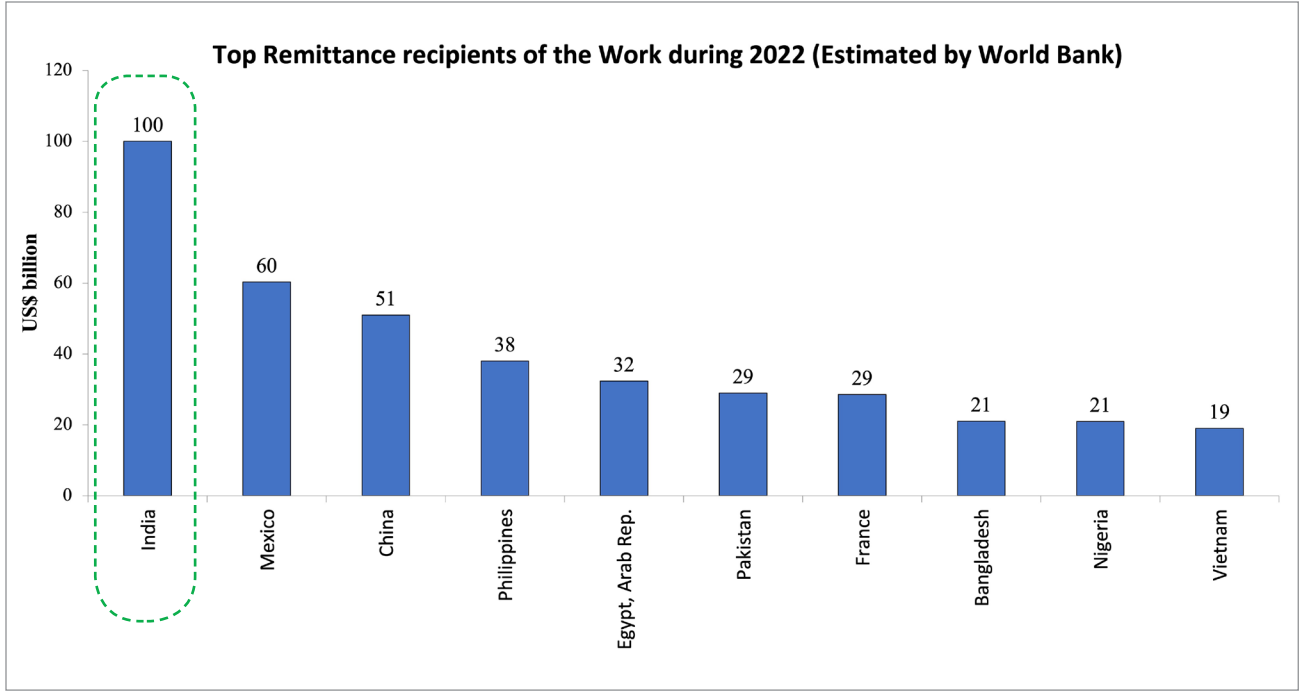
वैश्विक सेवाओं में भारत का स्थान

- 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक
- विश्व निर्यात का 4%
- वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 23 तक (अप्रैल-सितंबर) निर्यात में 27.9 प्रतिशत वृद्धि
- नेट सेवा निर्यातों का पूर्व कोविड अधिकतम योगदान साफ्टवेयर सेवाओं से आया। तथापि गैर-साफ्टवेयर सेवाओं की श्रेणियों ने कोविड के बाद अधिक योगदान दिया

सुदृढ़ एफडीआई और एफपीआई की वापसी

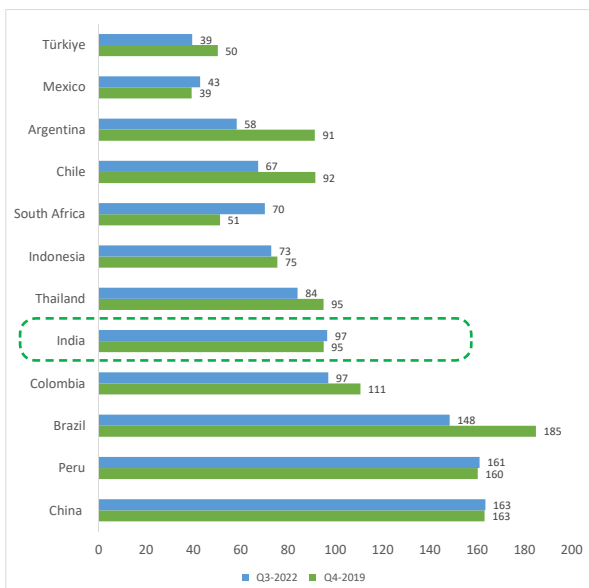


सेवा निर्यात के बाद धन प्रेषण बाह्य वित्त का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है

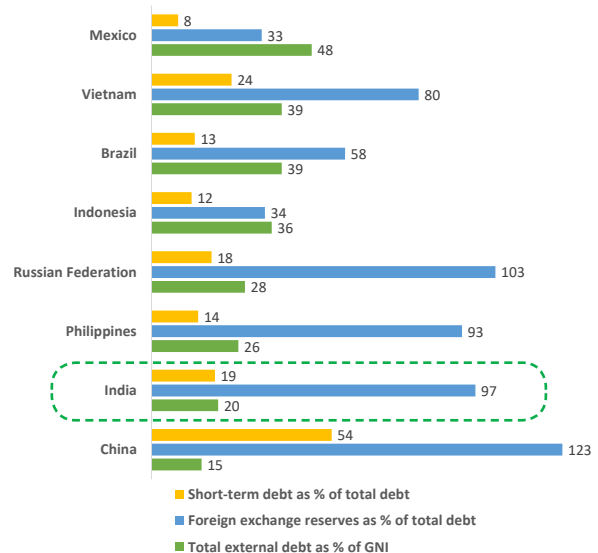


मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में भारत सुदृढ़ स्थिति में है

- 9.3 महीनों के आयातों के लिए यूएस \$563 बिलियन का फॉरेक्स रिज़र्व पर्याप्त है (दिसंबर 2022 के अनुसार)
- भारत के फॉरेक्स रिज़र्वों की पर्याप्तता (वार्षिक निर्यातों के प्रतिशत के अनुसार): साथी देशों की तुलना के दृष्टिकोण में



- भारत सापेक्ष रूप से सकल राष्ट्रीय आय के प्रतिशत और कुल ऋण का वर्तमान स्टॉक विदेशी विनिमय रिज़र्वों के सहज स्तर पर होने के कारण भली भांति सुरक्षित है।
- भौतिक और डिजिटल अवसंरचना: संभावित विकास को बढ़ाना



अवसंरचना विकास के लिए सरकार का दृष्टिकोण

अवसंरचना विकास के लिए सरकार का दृष्टिकोण

सार्वजनिक निजी भागीदारी

- वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक, वीजीएफ योजना के तहत, 57,870.1 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत वाली 56 परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम' (आईआईपीडीएफ) को परियोजना-प्रायोजक प्राधिकरणों को निधीयन सहायता प्रदान करने के लिए अधि सूचित किया गया था।
- वित्त वर्ष 23-25 से ₹150 करोड़ परिव्यय के साथ आईआईपीडीएफ को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन

- कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत 141.4 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 89,151 परियोजनाएं।
- 5.5 लाख करोड़ रुपये की 1009 परियोजनाएं पूरी हुईं।
- एनआईपी और परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल का लिंकेज परियोजनाओं के लिए अनुमोदन/ मंजूरी को शीघ्र ट्रैक करेगा।

राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन

- संचयी निवेश क्षमता 9.0 लाख करोड़ रु. अनुमानित है।
- वित्त वर्ष 22 में 0.8 लाख करोड़ के मुद्रीकरण लक्ष्य के मुकाबले 0.9 लाख करोड़ हासिल किए गए हैं।
- एनएमपी का दूसरा वर्ष यानी वित्त वर्ष 23 का लक्ष्य 1.6 लाख करोड़ रु. (समग्र एनएमपी लक्ष्य का 27 प्रतिशत) है।

गतिशक्ति

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंत्रालयों/विभागों में एकीकृत योजना और समकालिक कार्यान्वयन के लिए व्यापक डेटाबेस है।
- इसका उद्देश्य लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण अंतराल को पाटते हुए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता में सुधार करना है।

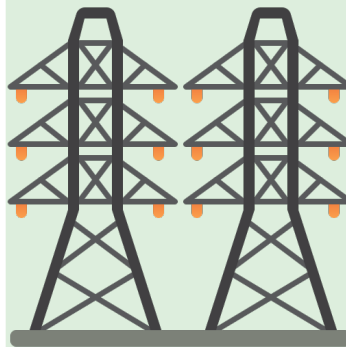
विद्युत क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा

सोलर पार्क



30 सितंबर 2022 तक, सरकार ने 16 राज्यों में 59 सौर पार्कों के विकास के लिए 40 गीगावाट की संपूर्ण 1 लक्ष्य क्षमता को मंजूरी दे दी है।

उत्पादित बिजली



वित्त वर्ष 22 के दौरान उत्पादित कुल बिजली वित्त वर्ष 21 के दौरान 15.9 लाख गीगावाट की तुलना में 17.2 लाख गीगावाट थी।

संस्थापित बिजली क्षमता



कुल क्षमता (1 मेगा वाट (मेगावाट) और उससे अधिक की मांग वाले उद्योग) 31 मार्च 2021 को 460.7 गीगावाट से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 482.2 गीगावाट हो गई।

भारतीय रसद को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना

राष्ट्रीय रसद नीति

एनएलपी का विजन त्वरित और समावेशी विकास के लिए देश में तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, संधारणीय और विश्वसनीय रसद पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

एनएलपी के लिए लक्ष्य:

- वर्ष 2030 तक भारत में रसद की लागत को वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करना।
- वर्ष 2030 तक रसद प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष 25 देशों में शामिल होना।
- एक कुशल रसद पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा-संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना।
- कार्यान्वयन व्यापक रसद कार्य योजना (सीएलएपी) के माध्यम से होगा।
- एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता मानकों की बेंचमार्किंग, स्टेट एंगेजमेंट, एक्जिम (निर्यात-आयात) लॉजिस्टिक्स, सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोमवर्क और लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास की सुविधा।



राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच)/सड़कों के निर्माण में तेजी से वृद्धि:

वित्त वर्ष 2016 में 6061 किमी की तुलना में वित्त वर्ष 22 में 10457 किमी एनएच/सड़कों का निर्माण किया गया।



पूँजीगत व्यय पर नए सिरे से जोर देना:

बजट व्यय वित्त वर्ष 20 में 1.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 2.4 लाख करोड़ रुपये हो गया।

किसान रेल सेवाएं: दिनांक 22 अक्टूबर तक 2,359 रेल, लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई की।



पैसेंजर और एयर ट्रैफिक प्री-कोविड लेवल के 91 फीसदी पर पहुंचा:

वर्ष 2016 में उड़ान योजना की शुरुआत के बाद से अब तक एक करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है।



8 साल में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता लगभग दोगुनी हुई :

पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस 1x) का डिजिटाइजेशन, रेडियोफ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) समाधान सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लागू किया गया है।



जहाजों की परेशानी मुक्त आवाजाही के लिए विधायी संशोधन:

अंतर्देशीय जल परिवहन अधिनियम, 2021 ने बड़े पैमाने पर माल की आवाजाही के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 100 साल पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।

भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कहानी

विकास चालक

अनकल जनसांख्यिकी

मध्य वर्ग का विस्तार

डिजिटल बेहवियोर पैटर्न

डिजिटल सशक्तिकरण के लिए टेलीफोन और रेडियो



भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 117.8 करोड़ (सितंबर, 22 तक) है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 44.3 प्रतिशत ग्राहक हैं।



कुल टेलीफोन ग्राहकों में से 98 प्रतिशत से अधिक वायरलेस टेलीफोनी से जुड़े हुए हैं।



22 मार्च को भारत में कुल टेली-घनत्व 84.8 प्रतिशत था।



2015 और 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सदस्यता में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।



प्रसार भारती (भारत का स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक) - 479 स्टेशनों से 23 भाषाओं, 179 बोलियों में प्रसारण करता है। क्षेत्रफल के 92 प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या के 99.1 प्रतिशत तक इसका प्रसारण पहुँचता है।

डिजिटल सार्वजनिक सामान



किफायती पहुंच (आधार)

2009 में आधार के लॉन्च के बाद से, डिजिटल यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है।



सरकारी योजनाएं

'MyScheme', MyScheme, TrEDS, GEM, e-NAM, UMANG ने बाजार की जगह को बदल दिया है और नागरिकों को सभी क्षेत्रों में सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है।



युनिफाइड, पेमेंट इंटरफेस

वर्ष 19-22 में, UPI-आधारित लेनदेन का मूल्य (121 प्रतिशत) और मात्रा (115 प्रतिशत) दोनों बढ़े, और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।



डिजिटल कामर्स के लिए ओपन नेटवर्क

विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए सभी उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स परिदृश्य को अधिक समावेशी, सुलभ और अनुभव-संचालित बनाना।



अकाउंट एग्रीगेटर

सहमति-आधारित डेटा साझाकरण ढांचा वर्तमान में 110 करोड़ से अधिक बैंक खातों में है।



ओपन क्रेडिट सक्षम नेटवर्क

एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण अनुप्रयोगों की अनुमति देते हुए ऋण देने के कार्यों का लोकतंत्रीकरण करना।



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

राष्ट्रीय एआई पोर्टल ने 1520 लेख, 262 वीडियो और 120 सरकारी पहल प्रकाशित की हैं। एआई को भाषा अवरोध पर काबू पाने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है उदाहरण 'भाशिनी'।



सुदृढ़ डेटा शासन

बढ़ी हुई उपयोगकर्ता गोपनीयता के लिए कानून पेश करना और मानक, खुले और इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।